सांध्य दैनिक

नई दृष्टिबिंदु

सच की शक्ति, जनता की दृष्टि

PRGI Reg No - CTHIN/25/A3746

सु-विचार

" आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को बदल नहीं सकते इसलिए सुकून से अपनी जिन्दगी जिएं और खुश रहें। ...!! "

अज्ञात...

वर्ष–01 अंक–102 | संपादक आलोक तिवारी | दुर्ग, शनिवार 02 मई 2026 | पृष्ठ 08 | मूल्य –2 रुपए

कला और संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में विश्व नृत्य दिवस पर विद्यार्थियों ने दी शानदार प्रस्तुति

नई दृष्टिबिंदु / खैरागढ़

राजकुमारी इंदिरा सिंह कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के नृत्य संकाय द्वारा विश्व नृत्य दिवस के उपलक्ष्य में नृत्यांजली कार्यक्रम का गरिमामय आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रो(डॉ.) लवली शर्मा ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रभारी कुलसचिव वेंकट रमन गुड़े उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संयोजन अधिष्ठाता नृत्य संकाय प्रो.(डॉ.) नमन दत्त ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती के तैलचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ तत्पश्चात अतिथियों का अभिनंदन किया गया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के क्रम में कथक विभाग की डॉ.मंजरी बख्शी एवं डॉ. गुजन तिवारी अतिथि व्याख्याता के

निर्देशन में विद्यार्थी सचिन, तनुश्री, कल्पना, पायल, अपिर्ता, रंगीना, पुंखा, सोनाली, चांदनी, प्रिया, मेघा, नंदिनी, अंतरा एवं यशस्वी द्वारा सामूहिक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई।

इसी अनुक्रम में भरतनाट्यम विभाग की शोधार्थी बिंदु नायर के निर्देशन में छात्रा रोशनी, गरिमा, साक्षी, प्रीति, कुसुम, अनुपमा, कीर्ति, मानसी, पल्लवी, खुशबू, श्रुति एवं ज्योति द्वारा सामूहिक नृत्य की प्रस्तुति दी गई। साथ ही ओडिसी विभाग की छात्रा प्रज्ञा गोस्वामी के निर्देशन में छात्रा प्रज्ञा, हिमानी, दुर्गा, मीरा, डॉली, सोनाली, अंजली एवं रीना के द्वारा उत्कृष्ट सामूहिक नृत्य की प्रस्तुति दी गई। संपूर्ण कार्यकम का निष्पादन नृत्य संकाय के शिक्षकों एवं शोधार्थियों के कुशल मार्गदर्शन एवं निर्देशन में संपन्न हुआ।

इस अवसर पर नृत्य संकाय से डॉ. शिवाली सिंह (सहायक प्राध्यापक, कथक विभाग), डॉ. शेख मेदिनी होम्बल (सहायक प्राध्यापक, भरतनाट्यम विभाग), सुशांत कुमार दास (सहायक प्राध्यापक, ओडिसी विभाग) तथा अतिथि व्याख्याता डॉ. गुंजन तिवारी, डॉ. मंजरी बख्शी एवं होरिल गौर उपस्थित थे। अन्य संकायों से डॉ. हरिओम हरि (सहायक प्राध्यापक, अवनद्ध विभाग) एवं विवेक नवरे (सहायक प्राध्यापक, तंत्रीवाद्य विभाग) सहित बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के विद्यार्थी एवं शोधार्थी उपस्थित रहे।

भाजपा पार्षद दल 4 मई को नगर निगम में करेगा जोरदार प्रदर्शन

जिला भाजपा संगठन ने बनाई व्यापक रणनीति

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

आगामी 4 मई को निगम भिलाई के महापौर परिषद द्वारा विगत साढ़े चार वर्षों में किए गए कथित भ्रष्टाचार एवं दमनकारी नीतियों के विरोध में भाजपा जिला भिलाई के नेतृत्व में भाजपा पार्षद दल द्वारा जंगी धरना–प्रदर्शन किया जाएगा। इस संबंध में पूर्व तैयारी हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक भाजपा जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन की अध्यक्षता में हुई।

बैठक में भाजपा कार्यसमिति सदस्य ब्रजेश बिचपुरिया, वीरेंद्र साहू, ऊषा बारले, दिव्या भसीन, कवर्धा जिला प्रभारी महेश वर्मा, प्रदेश विशेष आमंत्रित सदस्य शिरीष अग्रवाल, समिति संयोजक श्याम सुंदर राव, नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा, उपनेता प्रतिपक्ष दया सिंह तथा जिला महामंत्री श्रीमती सुषमा जेठानी सहित अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक का संचालन जिला महामंत्री मनीष अग्रवाल ने किया एवं आभार प्रदर्शन जिला उपाध्यक्ष नटवर ताम्रकार ने किया।

जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन ने अपने उद्बोधन में कहा कि भिलाई नगर निगम में बीते साढ़े चार वर्षों में विकास कार्यों की अनदेखी कर केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया है। जनता की मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी करते हुए मनमानी और दमनकारी नीति अपनाई गई है, जिसके विरोध में भाजपा सड़कों पर उतरकर जनआवाज बुलंद करेगी। देवांगन ने बताया है कि उस जंगी धरनाझ्रप्रदर्शन में लगभग 5 हजार जनता वो कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे।

ब्रजेश बिचपुरिया ने कहा कि नगर निगम में पारदशिर्ता पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है और जनप्रतिनिधियों की आवाज को दबाने का प्रयास हो रहा है। भाजपा इस अन्याय के खिलाफ मजबूती से खड़ी है। समिति संयोजक श्याम सुंदर राव ने कहा कि 4 मई का धरना–प्रदर्शन ऐतिहासिक होगा। इसकी व्यापक तैयारी की जा रही है और प्रत्येक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह आंदोलन जनहित की लड़ाई है,जिसमें बड़ी संख्या में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने कहा कि निगम में जनता की समस्याओं को लगातार नजर अंदाज किया गया है। भाजपा पार्षद दल ने हर स्तर पर आवाज उठाई, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो अब आंदोलन ही एकमात्र रास्ता बचा है। यह धरना प्रदर्शन जनता के हक और न्याय के लिए है। बैठक में सभी कार्यकर्ताओं से अपील की गई है की वे अधिक से अधिक संख्या में 4 मई के धरना प्रदर्शन में शामिल होकर इस जन आंदोलन को सफल बनाएं।

इस अवसर पर विजय जायसवाल, विजेंद्र सिंह, रविंद्र सिंह, राम उपकार तिवारी, उपकार चंद्राकर, द्वारिका चंद्रवंशी, दिनेश सिंह, गोपाल कृष्ण वर्मा, चन्ना केशवलु, त्रिलोचन सिंह, चंद्रकांता माण्डले, पूनम शुक्ला, हेमंत देवांगन, विनोद सिंह, मनोज तिवारी, भारती साहू, प्रेम लाल साहू, विजय सिंह, योगेंद्र सिंह, स्वीटी कौशिक, खगेश कोसरिया, तुलसी ध्रुव, राजेश श्रीवास्तव, मंडल अध्यक्षगणझ्र तरुण सिंह, रोहित साहू, शशिभगत, दीपक भौंडेकर, घनश्याम साहू, प्रशांत गुप्ता, ए गौरी शंकर व रामजी निर्मलकर सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व पार्षदगण उपस्थित थे ।

सचिव की कलेक्टरों को दो टूक : अवैध रेत खनन पर सख्ती से हो कार्रवाई

मुख्यमंत्री साय के निर्देशों के पालन में लापरवाही पर कलेक्टर होंगे जिम्मेदार

खनिज विभाग के सचिव पी. दयानंद ने रेत आपूर्ति करने वाले प्रमुख 11 जिलों के कलेक्टरों के साथ की बड़ी वर्चुअल बैठक

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

छत्तीसगढ़ सरकार सुशासन और पारदर्शिता के अपने संकल्प के अनुरूप कार्य करते हुए खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर सख्ती से अमल कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि राजस्व क्षति और अवैध गतिविधि से जुड़े किसी भी मामले में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। साथ ही उन्होंने आम लोगों को उचित दरों पर रेत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर खनिज विभाग लगातार सक्रिय है और समय–समय पर इसकी समीक्षा भी की जा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री के सचिव सह खनिज विभाग के सचिव पी. दयानंद ने 30 अप्रैल 2026 को प्रदेश में रेत आपूर्ति करने वाले प्रमुख 11 जिलों—रायपुर, बिलासपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर–चांपा, सक्ती, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–बैकुंठपुर, बलरामपुर और कांकेर—के कलेक्टरों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक लेकर खदानों के संचालन की गहन समीक्षा की।

बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि प्रदेश में रेत की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। सभी स्वीकृत रेत खदानों से उनकी क्षमता के अनुरूप उत्पादन सुनिश्चित किया जाए और आम जनता को रेत उचित दरों पर उपलब्ध हो। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को रॉयल्टी मुक्त रेत उपलब्ध कराने के आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि इसकी आड़ में अवैध खनन को बढ़ावा न मिले।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि खनिज विभाग के केंद्रीय उड़नदस्ता दल को किसी जिले में अवैध खनन पर कार्रवाई करनी पड़ रही है, तो यह संबंधित जिला प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है कि वे इस मामले को लेकर गंभीर नहीं हैं। सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री पहले भी इस तरह की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जता चुके हैं।

बैठक के अंत में खनिज सचिव पी. दयानंद ने दो टूक कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। प्रदेश के किसी भी जिले में यदि अवैध खनन कार्य चल रहा हो और वहाँ ड्रोन सर्वे से अथवा केन्द्रीय उड़न दस्ता के दल द्वारा जाँच में अवैध उत्खनन का साक्ष्य पाया जाता है तो जिला कलेक्टर व खनिज अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी जिसके लिए वे स्वयं ज़िम्मेदार होंगे ।

साप्ताहिक समीक्षा अनिवार्य रूप से की जाए–पी दयानंद

खनिज सचिव दयानंद ने रेत खदानों की नीलामी प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए पाया कि गरियाबंद, कांकेर और जांजगीर–चांपा जिलों में 100 प्रतिशत से अधिक नीलामी की गई है, जबकि धमतरी, बिलासपुर और मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–बैकुंठपुर में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। इस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित कलेक्टरों को तत्काल अधिक से अधिक खदानों की नीलामी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सचिव ने यह भी निर्देशित किया कि नीलाम किए गए घाटों की खनन योजना और पर्यावरण स्वीकृति की प्रक्रिया को प्राथमिकता से पूर्ण किया जाए और इसकी साप्ताहिक समीक्षा अनिवार्य रूप से की जाए। साथ ही अवैध खनन वाले क्षेत्रों का चिन्हांकन कर सतत कार्रवाई की जाए तथा शिकायतों और मीडिया में प्रकाशित खबरों को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

चमत्कार के नाम पर मौत : किशोरी की जान लेने वाली महिला को मिली उम्रकैद की सजा

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

राजिम थाना क्षेत्र में चमत्कार और झाड़–फूंक के नाम पर एक किशोरी की मौत के मामले में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश पंकज सिन्हा की एट्रोसिटी कोर्ट ने दोषी महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला अंधविश्वास, जबरन धर्म परिवर्तन और अमानवीय उपचार से जुड़ा हुआ है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मूलत: भाटापारा निवासी ईश्वरी साहू के खिलाफ पंडरी निवासी सुनीता सोनवानी ने 23 मई 2025 को राजिम थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। सुनीता की बेटी मानसिक रूप से अस्वस्थ थी और उसका इलाज पहले रायपुर के निजी अस्पताल तथा बाद में महासमुंद मेडिकल कॉलेज में कराया गया था।

चमत्कारिक इलाज का झांसा : परिजनों को किसी परिचित के माध्यम से ईश्वरी साहू का संपर्क मिला, जिसने कथित तौर पर प्रभु के चमत्कारिक तेल और गर्म पानी से इलाज का दावा किया। आरोप है कि महिला ने किशोरी के शरीर पर तेल डालकर उस पर गर्म पानी डाला और पैरों से दबाव बनाकर मसाज किया।

धर्म परिवर्तन का दबाव : जब किशोरी की हालत में सुधार नहीं हुआ, तो आरोपी महिला ने परिजनों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। शिकायत के अनुसार, भय और भ्रम का माहौल बनाकर परिवार को किसी से चर्चा न करने की हिदायत भी दी गई।

पोस्टमार्टम में हुए चौंकाने वाले खुलासे : मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने गंभीर तथ्यों को उजागर किया। रिपोर्ट के मुताबिक, छाती पर दबाव और चोट के कारण फेफड़ों में रक्त जमा हो गया था, जिससे सांस रुकने से किशोरी की मौत हुई। इसके अलावा पसलियों में फ्रैक्चर और किसी भारी वस्तु से चोट के भी संकेत मिले।

अदालत का सख्त रुख : अदालत ने पूरे घटनाक्रम को गंभीर आपराधिक कृत्य मानते हुए दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अंधविश्वास और झूठे उपचार के नाम पर किसी की जान से खिलवाड़ करना गंभीर अपराध है। यह मामला एक बार फिर समाज में फैले अंधविश्वास और फर्जी उपचार पद्धतियों पर सवाल खड़ा करता है।

गूगल बॉय रुद्र को, लोक भवन में राज्यपाल रमेन डेका ने किया सम्मान

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका से लोक भवन में जिला दुर्ग के 6 वर्षीय 'गूगल बॉय' रुद्र शर्मा ने अपने पालकों के साथ मुलाकात की।अपनी अद्भुत स्मरण शक्ति से उसने हैरान कर दिया। राज्यपाल से मुलाकात के दौरान रुद्र ने सामान्य ज्ञान और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े सवालों के सटीक उत्तर देकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। कक्षा पहली के छात्र रुद्र को यूपीएससी और पीएससी स्तर के प्रश्नों के उत्तर भी याद हैं। मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने उससे छत्तीसगढ़ के गठन, राज्य की विशेषताओं और भारतीय संविधान से जुड़े प्रश्न पूछे, जिनका रुद्र ने बिना झिझक तुरंत सही जवाब दिया। रुद्र की तेज स्मरण शक्ति और आत्मविश्वास से प्रभावित होकर राज्यपाल ने उसकी सराहना की। उन्होंने लोक भवन की ओर से रुद्र को प्रमाण पत्र प्रदान किया और उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर रुद्र के माता श्रीमती पायल शर्मा के साथ उसके नाना विनोद शर्मा भी उपस्थित थे, जिन्होंने उसकी उपलब्धि पर खुशी जाहिर की।

सोमनी में नवीन पंचायत भवन के लिए बीस लाख रुपए की मिली स्वीकृति, ग्रामीणों में हर्ष

नई दृष्टिबिंदु / सोमनी

राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख ग्राम सोमनी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सामने आई है। ग्राम में नवीन पंचायत भवन निर्माण हेतु माननीय डॉ. रमन सिंह (विधायक एवं अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा) द्वारा 20 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

ज्ञातव्य है कि 24 अप्रैल 2026 को स्पीकर हाउस कार्यालय, राजनांदगांव में विधायक प्रतिनिधि संतोष अग्रवाल की अध्यक्षता में भाजपा ग्रामीण मंडल सोमनी के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में भाजपा ग्रामीण मंडल सोमनी के महामंत्री रमन सिंह राजपूत द्वारा ग्राम की विभिन्न समस्याओं को लिखित रूप में प्रस्तुत करते हुए विस्तार से अवगत कराया गया एवं ज्ञापन सौंपा गया।

इस दौरान यह भी उल्लेख किया गया कि पूर्व में अभिषेक सिंह (पूर्व सांसद) ने अपने संसदीय कार्यकाल में सोमनी आगमन के दौरान प्राप्त ज्ञापन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पंचायत भवन हेतु राशि स्वीकृत करवाई थी, किन्तु बाद में कांग्रेस शासनकाल में वह राशि निरस्त कर दी गई थी।

महामंत्री रमन सिंह राजपूत के आग्रह को गंभीरता से लेते हुए डॉ. रमन सिंह के निर्देशन में जनहित एवं ग्राम विकास को प्राथमिकता देते हुए नवीन पंचायत भवन निर्माण के लिए पुनः 20 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। इस स्वीकृति से ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों में हर्ष का माहौल है। इस अवसर पर रमन सिंह राजपूत (महामंत्री, भाजपा ग्रामीण मंडल सोमनी) ने डॉ. रमन सिंह, विधायक प्रतिनिधि संतोष अग्रवाल जी, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह तथा जिला भाजपा अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत के प्रति आभार व्यक्त किया है।

10वीं पास नहीं हुआ तो फंदे पर झूला युवक

बालोद। डौंडी थाना क्षेत्र के बंधिया पारा में 10वीं कक्षा में लगातार दो साल फेल होने से परेशान नाबालिग युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। मृतक की पहचान राजवीर बघेल (उम्र 17 साल) के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक, राजवीर पिछले दो वर्षों से 10वीं की परीक्षा में असफल हो रहा था। पहले साल वह 6 विषयों में फेल हुआ था। इस वर्ष भी 5 विषयों में असफल रहने के कारण वह काफी तनाव में था। बताया जा रहा है कि इसी मानसिक दबाव के चलते उसने यह आत्मघाती कदम उठा लिया। परिजनों ने जब उसे फंदे पर लटका देखा तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही डौंडी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

सुशासन तिहार-जन समस्या निवारण शिविर का आगाज हुआ वार्ड न. 01 से

कलेक्टर सिंह और महापौर बाघमार ने शिविर का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए निर्देश

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

जिले में सुशासन तिहार-2026 के अंतर्गत जन समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु आयोजित समाधान शिविरों की श्रृंखला का शुभारंभ आज नगर निगम दुर्ग के चंद्रशेखर आजाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पंचशील नगर से हुआ। शिविर के पहले ही दिन बड़ी संख्या में नागरिकों की भागीदारी देखने को मिली और कई समस्याओं का मौके पर ही निराकरण कर हितग्राहियों को राहत प्रदान की गई। शिविर का निरीक्षण कलेक्टर अभिजीत सिंह एवं महापौर श्रीमती अलका बाघमार द्वारा किया गया।

उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की तथा अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक प्राप्त आवेदन का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। पहले दिन कुल 196 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 145 मांग एवं 51 शिकायतें शामिल हैं। प्राप्त सभी आवेदनों को संबंधित विभागों को निराकरण हेतु प्रेषित किया गया। साथ ही त्वरित कार्रवाई करते हुए 10 लर्निंग लाइसेंस एवं 1 राशन कार्ड का मौके पर ही वितरण कर हितग्राहियों को सीधा लाभ प्रदान किया गया।

शिविर का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं जैसे राशन कार्ड, आयुष्मान भारत योजना एवं उज्ज्वला योजना का लाभ शीघ्र उपलब्ध कराना तथा उनकी समस्याओं का स्थल पर ही समाधान करना है। पहले दिन की सफलता से यह स्पष्ट है कि सुशासन तिहार आम जनता के लिए अत्यंत उपयोगी पहल सिद्ध हो रहा है।

कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कहा कि शिविरों के माध्यम से प्रशासन जनता के द्वार तक पहुँच रहा है। सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि प्राप्त आवेदनों का शीघ्र एवं संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित करें, ताकि नागरिकों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। इस दौरान महापौर श्रीमती अलका बाघमार ने कहा कि नगर निगम का प्रयास है कि प्रत्येक नागरिक की समस्या का त्वरित एवं पारदर्शी समाधान हो।

सुशासन तिहार के माध्यम से हम शासन की योजनाओं को सीधे जनता तक पहुँचाने और उनकी समस्याओं का मौके पर निराकरण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस अवसर पर आयुक्त सुमित अग्रवाल, एडीएम वीरेन्द्र सिंह, अपर कलेक्टर श्रीमती योगिता देवांगन, एसडीएम हरवंश सिंह मिरी, अतिरिक्त तहसीलदार श्रीमती क्षमा यदु, सभापति श्याम शर्मा, देवनारायण चन्द्राकर, शेखर चन्द्राकर, ज्ञानेश्वर ताम्रकर, शरीफ साहू, गोविंद देवांगन, सुरूचि उमरे, कार्यपालिन अभियंता सुश्री विनीता वर्मा, प्रकाश चंद थवानी, मो. सलीम सिद्दीकी, सहायक अभियंता गिरीश दिवान, संजय ठाकुर सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

खास खबर

21 कुम्हारों को इलेक्ट्रिक चाक, 200 ई-रिक्शा चालकों को आर्थिक सहायता

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर दुर्ग स्थित सेवा सदन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने अपने कर कमलों से हितग्राहियों को इलेक्ट्रिक चाक और अनुदान राशि का चेक वितरित किया। छत्तीसगढ़ माटीकला बोर्ड (ग्रामोद्योग विभाग) के माध्यम से दुर्ग जिले के 21 पंजीकृत कुम्हारों को निःशुल्क इलेक्ट्रिक चाक वितरित किए गए। इस योजना से प्रत्येक परिवार के तीन सदस्य लाभान्वित होंगे, जिससे कुल 63 लोगों को स्वरोजगार से जुड़ने का अवसर मिलेगा।

इसके साथ ही कार्यक्रम में 200 ई-रिक्शा चालकों को पांच-पांच हजार रुपये की स्वेच्छानुदान राशि भी प्रदान की गई। इस सहायता से चालकों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार श्रमिकों और छोटे व्यवसायियों को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य कर रही है, ताकि हर हाथ को रोजगार मिल सके। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड के प्रबंधक श्री साकेत, सुरेन्द्र कौशिक, शिवेन्द्र परिहार, कमलेश फेकर, बंटी हरीश चौहान, कौशल साहू, महेन्द्र लोहा, कुंभकार समाज के अध्यक्ष इंद्र कुंभकार, पार्षद मनीष साहू एवं गोविंद देवांगन उपस्थित थे।

'आरंभ' की ओर से राज्य स्तरीय काव्य पाठ एवं कविता पर संवाद चर्चा का आयोजन

भिलाई। प्रगतिशील जन-विचारधारा की साहित्यिक संस्था 'आरंभ' के तत्वाधान में पीजी नर्सिंग कॉलेज में राज्य स्तरीय काव्य पाठ एवं कविता पर संवाद चर्चा का आयोजन किया गया।

मुख्य अतिथि व्यंग्यकार कवि रवि श्रीवास्तव थे। पीजी नर्सिंग कॉलेज की प्राचार्या डॉ। रोजा प्रिंसी ने अध्यक्षता की। कविताओं पर संवाद चर्चा कल्याण महाविद्यालय हिंदी विभाग के सहायक प्राध्यापक व प्रगतिशील युवा कवि डॉ। अंजन कुमार थे। 'आरंभ' के मुख्य सलाहकार संस्कृत विद्वान आचार्य डॉ महेशचंद्र शर्मा, मुख्य संरक्षक कैलाश जैन बरमेचा और कॉलेज की उप प्राचार्य डॉ जी हेमावती उपस्थित थे। स्वागत उद्बोधन 'आरंभ' के अध्यक्ष प्रदीप भट्टाचार्य, संचालन महासचिव नूरुस्सबाह 'सबा' एवं आभार व्यक्त कार्यकारी अध्यक्ष डॉ रजनी नेलसन ने दिया।

इस अवसर पर पीजी नर्सिंग कॉलेज की तरफ से डॉ जी हेमावती, चंद्रकला लिल्हारे, सुश्मिता रॉय, नूतन निराला, डॉली सिन्हा, निक्की तिवारी, पूजा सोनवानी, भावना साहू, शिल्पी नंदी, आफसा बानो, कुमारी पावनी, प्रियंका सिन्हा और 'आरंभ' की तरफ से अनिता करडेकर, दीप्ति श्रीवास्तव, मिताली श्रीवास्तव वर्मा, फरीदा शाहीन अंसारी, शशिप्रभा गुप्ता, प्रकाशचंद्र मण्डल, पल्लव चटर्जी, शुभेंदु बागची, विपुल सेन, डॉ। विजय कुमार गुप्ता 'मुन्ना', राकेश गुप्ता 'रुसिया', सुशील यादव, त्रयंबक राव साटकर 'अंबर', जाविद हसन, डॉ नौशाद अहमद सिद्दीकी 'सब्र', डॉ इकबाल खान 'तन्हा', नवेद रजा दुगर्वी और शौकत इकबाल ने रचनाएँ पढ़ी।

प्रारंभ में अतिथियों द्वारा सरस्वती वंदना एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में श्रीमती शेफाली भट्टाचार्य, दिनेश कुमार मिश्रा, जसवंत कुमार मंडावी, जितेंद्र कुमार पटेल, श्रीमिनी पिछाई, सीमा संतोष, प्रेरणा बाघ, अपर्णा मोहतेवार, श्रीमती रोमा, श्रीमती ऐश्वर्या, 'आरंभ' एवं कॉलेज के सदस्य, छात्राएं और टीचर उपस्थित थे। यह जानकारी 'प्रवक्ता' जाविद हसन ने दी।

श्रमिक दिवस : सेवा सदन में श्रमिकों का सम्मान मंत्री गजेन्द्र यादव ने श्रमिकों के साथ किये भोजन

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर दुर्ग स्थित सेवा सदन में गरिमामय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहाँ प्रदेश के केबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव ने श्रमिक साथियों के साथ सादगीपूर्ण वातावरण में बैठकर भोजन किये और उनके दैनिक जीवन से जुड़े विभिन्न विषयों पर संवाद किये।

कार्यक्रम के दौरान मंत्री गजेन्द्र यादव ने श्रमिकों के साथ जमीन से जुड़ी समस्याओं पर खुलकर चर्चा किये। उन्होंने श्रमिकों से रोजगार की स्थिरता, दैनिक आय, श्रम परिस्थितियों, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, आवास, शिक्षा और जरूरतों से संबंधित विषयों पर विस्तार से जानकारी लिए। श्रमिकों ने भी अपने अनुभव, परेशानी और अपेक्षाएं साझा कर उन्हें जानकारी दिए, जिसे मंत्री ने गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के माध्यम से समाधान सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया।

कार्यक्रम में शिक्षा, ग्रामोद्योग एवं विधी विधायी मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि श्रमिक हमारे समाज की रीढ़ हैं। उनके परिश्रम और समर्पण से ही विकास की मजबूत नींव तैयार होती है। श्रमिकों का सम्मान केवल एक दिवस तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रतिदिन सम्मान होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए निरंतर कार्य कर रही है। श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विस्तार, श्रमिकों के कौशल विकास, स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

इस अवसर पर मंत्री श्री यादव ने प्रदेश में आज से प्रारंभ हो रहे सुशासन तिहार की भी जानकारी दिए। उन्होंने बताया कि यह अभियान आम नागरिकों, विशेषकर श्रमिक वर्ग की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से शुरू किया गया है। शिविरों के माध्यम से लोगों की शिकायतें सीधे दर्ज की जाएंगी और उनका समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। कार्यक्रम में उपस्थित श्रमिकों ने मंत्री के साथ बैठकर भोजन करने के इस सादगीपूर्ण और आत्मीय पहल की सराहना किये। उन्होंने कहा कि इस तरह का संवाद उन्हें शासन से सीधे जुड़ने का अवसर देता है और उनकी आवाज को मजबूती मिलती है। मंत्री गजेन्द्र यादव ने सभी श्रमिकों को श्रमिक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उनका उत्साहवर्धन किये।

मुख्य न्यायाधिपति के मार्गदर्शन में श्रमिकों को दी गई विधिक अधिकारों की जानकारी

अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के पावन अवसर पर, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा जिले के विभिन्न स्थानों पर व्यापक स्तर पर विधिक जनजागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया।

उल्लेखनीय है कि मुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा द्वारा समय-समय पर यह निर्देशित किया गया है कि समाज के कमजोर एवं वंचित वर्ग, विशेषकर श्रमिकों, को गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना न्याय प्रणाली की प्राथमिक जिम्मेदारी है तथा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक या सामाजिक कारणों से न्याय से वंचित न रह जाए। इसके अतिरिक्त, मुख्य न्यायाधिपति द्वारा राज्य में आयोजित नेशनल लोक अदालतों के माध्यम से लाखों प्रकरणों के त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निराकरण पर विशेष बल दिया गया है, जिससे श्रमिकों एवं आम नागरिकों को शीघ्र न्याय प्राप्त हो सके तथा विवादों का प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके। इसी क्रम में, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के विशेष अवसर पर जिला दुर्ग में आयोजित विधिक जागरूकता शिविरों का मुख्य उनके विधिक अधिकारों, श्रम संबंधी कानूनों, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं एवं निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में जागरूक करना रहा। सेठ रतनवद सुराना लॉ कॉलेज, दुर्ग में आयोजित विशेष विधिक जागरूकता शिविर में तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा श्रमिकों के अधिकारों, विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत प्राप्त संरक्षण, कार्यस्थल पर उपलब्ध सुविधाओं तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में सरल, प्रभावी एवं व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान किया गया। अपने उद्बोधन में उन्होंने श्रमिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक रहने तथा किसी भी प्रकार के शोषण, भेदभाव या अन्याय की स्थिति में विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया। उक्त कार्यक्रम में अष्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, प्रावार्य अखिलेश अग्रवाल, अधिवक्तागण एवं श्रम विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में केंद्रीय जेल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के पैरालीगल वॉलंटियर्स (पीएलवी) एवं एलएडीसीएस कर्मचारियों द्वारा बनाई गई चित्रकला प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसे उपस्थित सभी लोगों ने सराहा। इसके अतिरिक्त, जिले के अन्य स्थानों पर भी न्यायाधीशगण एवं पैरालीगल वॉलंटियर्स द्वारा विधिक जागरूकता शिविर आयोजित कर नागरिकों एवं श्रमिकों को श्रम कानूनों, विधिक अधिकारों एवं निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। पैरालीगल वालंटियर्स द्वारा पॉम्पलेट वितरण, जनसंवाद, व्यक्तिगत परामर्श एवं जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से आमजन तक सरल भाषा में विधिक जानकारी पहुंचाने का सराहनीय कार्य किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा उपरोक्त विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन कर यह सुनिश्चित करने का सुदृढ़ कदम उठाया गया कि समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर श्रमिक वर्ग, तक विधिक सेवाएं सुलभ एवं प्रभावी रूप से पहुँच सके।

स्वच्छता मित्रों व सफाई कर्मचारियों का किया गया सम्मान

अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा शहर की स्वच्छता व्यवस्था की आधारशिला माने जाने वाले स्वच्छता मित्रों एवं समस्त सफाई कर्मचारियों के सम्मान में विशेष स्नेह भोज का आयोजन किया गया। यह आयोजन न केवल सम्मान का प्रतीक रहा, बल्कि जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों के बीच आत्मीय जुड़ाव का भी सशक्त माध्यम बना। मोतीलाल वोरा सभागार एवं कुशाभाउ ठाकरे भवन, आदित्य नगर में आयोजित इस कार्यक्रम में महापौर अलका बाघमार, सभापति श्याम शर्मा सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने स्वच्छता मित्रों व वाहन चालक के साथ बैठकर भोजन किया और उनके योगदान के प्रति आभार व्यक्त किया।

नगर निगम प्रशासन द्वारा किया गया यह प्रयास उन कर्मठ हाथों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है, जो प्रतिदिन कठिन परिश्रम कर शहर को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश भी दिया गया कि समाज के हर वर्ग का योगदान समान रूप से महत्वपूर्ण है।

महापौर अलका बाघमार ने इस अवसर पर सभी स्वच्छता कर्मियों को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शहर की स्वच्छता और स्वास्थ्य व्यवस्था में उनका योगदान अतुलनीय है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता मित्रों के बिना शहर की कल्पना अधूरी है और नगर निगम सदैव उनके हितों के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। सभापति श्याम शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि श्रमिकों का सम्मान करना केवल कर्तव्य ही नहीं, बल्कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। उन्होंने कहा कि श्रमेव जयते के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए हमें श्रमिकों के योगदान को सदैव स्मरण रखना चाहिए।

इस अवसर पर एमआईसी सदस्य शशि साहू, पार्षद विद्यावती सिंह, पार्षद सुरूचि उमरे, गुलशन साहू, मनीष कोठारी, सावित्री दमाहे, रंजीता पाटिल, गोविंद देवांगन, नीरा खिचरिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता, शिएव अहमद, संजय मिश्रा, अनिल सिंह, कुणाल, राहुल तथा स्वास्थ्य अमला टीम के सदस्य उपस्थित रहे।

गुजरात स्थापना दिवस पर भिलाई में सजी सांस्कृतिक संध्या, हास्य नाटक ने जीता दिल

सिविक सेंटर कला मंदिर में पहली बार गुजराती हास्य नाटक का मंचन, दर्शकों ने सराहा

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

सिविक सेंटर स्थित कला मंदिर में गुजरात स्थापना दिवस (1 मई) के अवसर पर श्री सकल गुजराती समाज दुर्ग जिला द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में इंद्रजीत सिंह छोटू ने सहभागिता निभाई। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में पहली बार प्रस्तुत किए गए गुजराती हास्य नाटक ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया।

कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति, कला और विविधता की सुंदर झलक देखने को मिली। रंगमंच के माध्यम से प्रस्तुत हास्य नाटक ने दर्शकों को हँसी के साथ-साथ सामाजिक संदेश भी दिया, जिसे खूब सराहा गया।

इस सफल आयोजन के लिए समाज के अध्यक्ष गिरिशभाई सांवरिया, कार्यकारी अध्यक्ष अनिलभाई पटेल, सचिव संजयभाई नथवानी, कोषाध्यक्ष राजेशभाई राजा सहित सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों को इंद्रजीत सिंह छोटू ने बधाई एवं धन्यवाद प्रेषित किया।

ऐसे सांस्कृतिक आयोजन भिलाई की बहुरंगी पहचान को मजबूत करते हुए ह्रमिनी इंडियाह्व की छवि को और सशक्त बनाते हैं।

ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क पर शिकंजा : बाबू खेमानी के करीबी समेत दो और आरोपी हुए गिरफ्तार

नई दृष्टिबिंदु / महासमुंद-दुर्ग

ऑनलाइन सट्टा गिरोह के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए पुलिस ने एक बड़ी कड़ी को और उजागर किया है। गिरफ्तार सटोरिया बाबू खेमानी से जुड़े नेटवर्क में उसके करीबी रिश्तेदार समेत दो आरोपियों को महासमुंद से गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी संदीप असरानी, बाबू खेमानी का रिश्तेदार (बुआ का बेटा) बताया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि संदीप असरानी अपने साथी के साथ मिलकर गिरोह को बैंक खाते और सिम कार्ड उपलब्ध कराने का काम करता था, जिनका इस्तेमाल ऑनलाइन सट्टा संचालन में किया जाता था।

जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि बाबू खेमानी से जब्त किए गए कुछ सिम कार्ड संदीप असरानी के नाम पर पंजीकृत हैं, जिससे उसके नेटवर्क में सक्रिय भूमिका की पुष्टि होती है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक, मामले में कई और खुलासे होने की संभावना है। पुलिस ने संकेत दिए हैं कि पूरे मामले का विस्तृत खुलासा जल्द ही किया जाएगा, जिसमें सट्टा नेटवर्क के संचालन, लेन-देन और अन्य संलिप्त व्यक्तियों की भूमिका सामने लाई जाएगी।

बरसात के पहले एटीआर क्षेत्र के गांवों में लगाएं मेगा स्वास्थ्य शिविर – मंत्री अरुण साव

जीवनदीप समिति के कर्मचारियों के मानदेय मे हुई वृद्धि, उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 50 बिस्तर अस्पताल में जीवन दीप समिति की हुई बैठक

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लोरमी स्थित 50 बिस्तर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अस्पताल में जीवन दीप समिति की साधारण समिति की बैठक उप मुख्यमंत्री अरुण साव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक से पहले उप मुख्यमंत्री ने अस्पताल का निरीक्षण भी किया। उन्होंने यहां उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं, साफ-सफाई की व्यवस्था एवं गार्डन की हरियाली की सराहना की। उन्होंने व्यवस्थाओं पर संतोष जताते हुए सेवाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए।

बैठक में एजेंडावार चर्चा करते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार एवं सुधार हेतु कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जीवन दीप समिति के कर्मचारियों के मानदेय में पांच वर्ष पूर्ण होने पर प्रतिमाह 2000 रुपये वृद्धि की स्वीकृति दी गई। साथ ही अस्पताल के सोलर सिस्टम की मरम्मत, बैटरी बदलने एवं जनरेटर सुधार के लिए डीएमएफ मद से प्रस्ताव तैयार कर कलेक्टर मुंगेली को भेजने के निर्देश दिए गए।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने अस्पताल में नए पेइंग वार्ड के निर्माण के लिए अपने विधायक मद से 20 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की। वहीं डीएमएफ मद से शव वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी स्वास्थ्य विभाग को दिए। निर्माणाधीन ब्लड बैंक एवं इंटीग्रेटेड लैब को शीघ्र पूर्ण करने तथा 50 बिस्तर अस्पताल को 100 बिस्तर में उन्नत करने के लिए अतिरिक्त भवन स्वीकृति हेतु शासन को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए। इसके लिए सहकारिता विभाग के पुराने गोदाम की भूमि स्वास्थ्य विभाग को आबंटित करने की प्रक्रिया तेज करने कहा गया।

बरसात से पूर्व एटीआर क्षेत्र के गांवों में मेगा स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने, खुड़िया बांध के पार स्थित गांवों के लिए बोट एम्बुलेंस प्रस्तावित तैयार करने तथा अस्पताल की सुरक्षा के लिए रात्रि में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने और दो सुरक्षा गार्ड रखने की स्वीकृति दी बैठक में दी गई। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने अस्पताल से अनावश्यक रिफरल केस को कम करने पर भी जोर देते हुए मरीजों को स्थानीय स्तर पर बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। लोरमी एसडीएम श्री अजीत पुजारी और डीपीएम श्री गिरीश कुर्रे सहित जीवन दीप समिति के सदस्य और विभागीय अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे।

खास खबर

शासकीय उचित मूल्य दुकान विक्रेता सरकार की मजबूत कड़ी : अरुण साव

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

उप मुख्यमंत्री अरुण साव लोरमी के मानस मंच में आयोजित प्रदेश स्तरीय शासकीय उचित मूल्य दुकान विक्रेता एवं संचालक संघ के सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में उन्होंने संघ को सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी व प्रभावी बनाने का श्रेय दिया। साथ ही उनकी 6 मांगों पर गंभीरता से चर्चा का आश्वासन दिया। उन्होंने संघ के सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए 15 लाख रुपए देने की घोषणा की। श्री साव ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली आम जनता के जीवन से सीधे जुड़ी हुई व्यवस्था है। आप हितग्राहियों तक समय पर राशन पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हजारों परिवारों के खाद्यान्न वितरण की जिम्मेदारी निभाते हैं। यह केवल एक कार्य नहीं है, यह सामाजिक दायित्व है। आप सभी की सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में महती भूमिका है।

गांवों में खत्म हो रहा शिकायतों का दौर, शिविर में उमड़ा जनसैलाब

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकार की 'सुशासन' को धरातल पर उतारने की कवायद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में 'सुशासन तिहार' के जरिए प्रशासन सीधे ग्रामीणों के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। शुक्रवार को ग्राम रिसदा से शुरू हुए इस अभियान ने पहले ही दिन सफलता के नए मानक स्थापित किए हैं।

इस अवसर पर राजस्व मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को मुस्कुराते हुए देखना है उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिविर के बाद भी आवेदकों से फीडबैक लिया जाए कि वे समाधान से संतुष्ट हैं या नहीं। रिसदा के हाई स्कूल प्रांगण में लगे शिविर की सबसे बड़ी विशेषता इसकी संवेदनशीलता रही। शिविर में आए 573 आवेदनों में से लगभग आधे का निराकरण राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा की मौजूदगी में अधिकारियों ने तुरंत किया। यह इस बात का प्रमाण है कि सरकारी मशीनरी अब फाइलों को अटकाने के बजाय सुलझाने पर ध्यान दे रही है। जिन आवेदनों में तकनीकी पेच हैं, उनके लिए कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने समय-सीमा निर्धारित कर दी है।

शिविर में केवल शिकायतें ही नहीं सुनी गईं, बल्कि शासन की कल्याणकारी योजनाओं का 'डिलीवरी सेंटर' भी बनाया गया। पुलिस विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा हेतु हेलमेट वितरण और भारत माता वाहिनी को संसाधन भेंट किए गए। इसी तरह युवाओं को कौशल विकास का सम्मान पत्र और टीबी मुक्त गांव के सरपंचों को महात्मा गांधी की प्रतिमा भेंट कर सामाजिक सहभागिता को सराहा गया। शिविर में स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल पर डिजिटल एक्स-रे और तत्काल आयुष्मान कार्ड बनाने की सुविधा ने बुजुर्गों और मरीजों को बड़ी राहत दी। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि यह केवल एक दिवसीय आयोजन नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित अभियान है। जिले के 30 ग्रामीण केंद्रों और 19 नगरीय निकायों में सुशासन तिहार के जरिए प्रत्येक नागरिक की पहुंच प्रशासन तक सुनिश्चित की जाएगी।

हर बूंद से अधिक उत्पादन की दिशा में बड़ा कदम

बगिया समृद्धि एम-कैड योजना से 13 गांवों के 4933 हेक्टेयर में होगी सिंचाई – मुख्यमंत्री साय

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले के गृह ग्राम बगिया में समृद्धि कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन आधुनिकीकरण (एम-कैड) योजना के अंतर्गत बगिया दाबित उद्वहन सिंचाई प्रणाली के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू एवं कृषि मंत्री रामविचार नेताम सहित जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बगिया समृद्धि एम-कैड योजना केवल एक सिंचाई परियोजना नहीं, बल्कि हर बूंद से अधिक उत्पादन की सोच का सशक्त प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इसके सफल क्रियान्वयन से जशपुर जिला देश के लिए आधुनिक दाबित सिंचाई प्रणाली का मॉडल बनेगा और किसानों को समृद्धि की नई दिशा मिलेगी।

उन्होंने कहा कि इस परियोजना के तहत पारंपरिक नहर प्रणाली के स्थान पर आधुनिक प्रेसराइज्ड पाइप इरिगेशन नेटवर्क विकसित किया जाएगा। भूमिगत पाइपलाइन व्यवस्था से जल का अपव्यय रुकेगा, जल उपयोग दक्षता बढ़ेगी और भूमि अधिग्रहण की समस्या भी नहीं आएगी। अब तक वर्षा पर निर्भर रहने वाले किसानों को इस योजना से वर्षभर सिंचाई हेतु पर्याप्त जल उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने कहा कि बगिया समृद्धि एम-कैड योजना न केवल सिंचाई व्यवस्था को आधुनिक बनाएगी, बल्कि कृषि को तकनीक आधारित, टिकाऊ और लाभकारी दिशा में आगे बढ़ाएगी। यह परियोजना जशपुर को राष्ट्रीय स्तर पर एक मॉडल एग्री-इरीगेशन डिस्ट्रिक्ट के रूप में स्थापित करने की क्षमता रखती है। उन्होंने कहा कि यह पहल हमारे अन्नदाताओं को समृद्धि, आत्मनिर्भरता और सम्मान की नई ऊँचाइयों तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करेगी।

उल्लेखनीय है कि यह परियोजना कांसाबेल विकासखंड के बगिया क्लस्टर में मैनी नदी पर बगिया बैराज सह दाबित उद्वहन सिंचाई योजना के माध्यम से लागू की जा रही है। इसके तहत बगिया, उसकुटी, रजोती, सुजीबहार, चोंगरीबहार, बांसबहार, डोकड़ा, सिकरिया, पतराटोली, गहिराडोहर, बीहाबल, नरियरडांड एवं ढुढुडांड सहित 13 गांवों के लगभग 4933 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि देश के 23 राज्यों में स्वीकृत 34 एम-कैड परियोजनाओं में छत्तीसगढ़ का बगिया क्लस्टर एकमात्र चयनित परियोजना है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा 95.89 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है, जबकि परियोजना की कुल लागत लगभग 119 करोड़ रुपये है।

इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि यह योजना क्षेत्र के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी और किसानों को स्थायी आय का आधार प्रदान करेगी। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने इसे किसानों के लिए आने वाले समय का वरदान बताते हुए कहा कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। समृद्धि योजना के स्टेट नोडल ऑफिसर आलोक अग्रवाल ने बताया कि एम-कैड कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2025 में किया गया था। उन्होंने बताया कि यह परियोजना अगले 6 माह में पूर्ण की जाएगी और इसके संचालन एवं संधारण की जिम्मेदारी प्रारंभिक 5 वर्षों तक ठेकेदार द्वारा तथा उसके बाद जल उपभोक्ता समिति द्वारा संभाली जाएगी। इस समिति में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है।

परियोजना में सौर ऊर्जा आधारित विद्युत आपूर्ति, SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) और IoT (Internet of Things) जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, जिससे जल का नियंत्रित और वैज्ञानिक उपयोग संभव होगा। डेटा आधारित प्रबंधन के माध्यम से यह तय किया जाएगा कि किस क्षेत्र में कब और कितनी मात्रा में पानी देना है। इस योजना का उद्देश्य जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना, प्रत्येक बूंद का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना तथा किसानों की आय में स्थायी सुधार लाना है। साथ ही उन्नत कृषि पद्धतियों के माध्यम से किसानों को जलवायु परिवर्तन से जुड़े जोखिमों से निपटने में सक्षम बनाया जाएगा।

प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार का आगाज, मंत्रिगणों ने शिविर में आम लोगों की समस्याएं सुनी

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

छत्तीसगढ़ में सुशासन की अवधारणा को जमीनी स्तर पर साकार करने की दिशा में आज एक मई से सुशासन तिहार 2026 का प्रदेशव्यापी शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में 01 मई से 10 जून तक संचालित होने वाला यह अभियान शासन और आमजन के बीच की दूरी को समाप्त कर पारदर्शी, त्वरित एवं संवेदनशील प्रशासन सुनिश्चित करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। अभियान के प्रथम दिवस प्रदेश के विभिन्न जिलों में जनसमस्या निवारण शिविरों का आयोजन किया गया, जहां मंत्रीगण, जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी स्वयं उपस्थित होकर आम नागरिकों की समस्याएं सुनते नजर आए। यह पहल वास्तव में राज्य के अंतिम व्यक्ति तक शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ पहुंचाने की छत्तीसगढ़ सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने का प्रभावी माध्यम है।

बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के ग्राम रिसदा में आयोजित शिविर में जनसैलाब उमड़ पड़ा। यहां प्राप्त 573 आवेदनों में से लगभग 47 प्रतिशत का मौके पर ही निराकरण किया गया। राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक आवेदन का समय-सीमा में निराकरण किया गया और आवेदकों से संतुष्टि फीडबैक भी लिया जाए। कोरबा जिले के कटघोरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम धनरास में आयोजित शिविर में 332 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 103 का तत्काल समाधान किया गया। वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि यह अभियान शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बन रहा है।

इसी क्रम में रायपुर जिले के अभनपुर विकासखंड के ग्राम कठिया में आयोजित शिविर में मंत्री गुरु खुशवंत साहेब की उपस्थिति में कई हितग्राहियों को शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया। महिलाओं को मनरेगा जॉब कार्ड प्रदान किए गए। दिव्यांग हितग्राही योगेश यादव को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई गई। शिविर में हितग्राहियों के चेहरे पर खुशी देखते ही बनती थी।

शिविरों में विभिन्न विभागों द्वारा वन-स्टॉप समाधान केंद्र के रूप में स्टॉल लगाए गए, जहां आमजन को आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, केसीसी ऋण, उज्ज्वला योजना, कृषि उपकरण, मत्स्य पालन सामग्री सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ मौके पर ही प्रदान किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा डिजिटल एक्स-रे जैसी सुविधाओं की उपलब्धता ने ग्रामीणों को त्वरित राहत दी। सुशासन तिहार के माध्यम से न केवल शिकायतों का निराकरण किया जा रहा है, बल्कि आम नागरिकों को शासन की योजनाओं के प्रति जागरूक कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय स्वयं इस अभियान की सतत मॉनिटरिंग कर रहे हैं तथा औचक निरीक्षण के माध्यम से जमीनी क्रियान्वयन की समीक्षा भी करेंगे।

योजनाओं का उठाएं लाभ और अपनी समस्याओं का आवेदन देकर कराएं निराकरण : मंत्री देवांगन

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

कोरबा जिले में सुशासन तिहार की शुरुआत कटघोरा ब्लॉक के ग्राम पंचायत धनरास से हुई। 01 मई से 10 जून तक आयोजित होने वाले इस तिहार के प्रथम दिवस आज जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें तेज धूप और गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पहुँचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

शिविर में विभागीय अधिकारियों द्वारा विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई तथा पात्र ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ उठाने हेतु प्रोत्साहित किया गया। ग्रामीणों ने भी अपनी मांगों एवं समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। प्राप्त कुल 332 आवेदनों में से 103 का निराकरण मौके पर ही कर दिया गया। कृषि, मत्स्य, समाज कल्याण, पंचायत, राजस्व, खाद्य एवं सहकारिता विभाग द्वारा इस दौरान हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया गया।

कार्यक्रम में प्रदेश के वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि सुशासन तिहार के माध्यम से आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान हो तथा उन्हें शासन की कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने बताया कि 01 मई से 10 जून तक जिले में कुल 37 शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें विभिन्न ग्राम पंचायतों को क्लस्टरवार शामिल किया गया है।

मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनेक जनकल्याणकारी योजनाएँ संचालित की गई हैं और राज्य में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में भी जनता को योजनाओं का निरंतर लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण अपने क्षेत्र में लगे शिविरों में आसानी से आवेदन देकर अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री

गरीबों को मुफ्त चावल, नल कनेक्शन, किसानों को सम्मान निधि तथा ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास जैसी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा धान बोनस, प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी, रामलला दर्शन, सरस्वती साइकिल योजना और महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार के दौरान मुख्यमंत्री किसी भी गाँव में अचानक पहुंचकर योजनाओं के वास्तविक क्रियान्वयन की जानकारी लेंगे।

कार्यक्रम में कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल ने कहा कि सुशासन तिहार ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान का प्रभावी माध्यम है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में नित नई विकास योजनाएँ बनाई जा रही हैं और उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँच रहा है। उन्होंने ग्रामीणों से अधिक से अधिक संख्या में शिविरों में भाग लेने की अपील की। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. पवन सिंह ने कहा कि एक ही स्थान पर सभी विभागों की उपस्थिति से ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने और उनका लाभ लेने में आसानी होती है। जनपद सदस्य श्रीमती झूल बाई गोविंद ने भी शिविर की सराहना की।

शिविर में प्रभारी कलेक्टर आशुतोष पांडे, जिला पंचायत सीईओ दिनेश नाग, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल, एसडीएम तन्मय खन्ना, जनपद सीईओ यशपाल सिंह सहित आसपास की ग्राम पंचायतों के सरपंच, जनप्रतिनिधि एवं भारी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टाल लगाया गया था जिसका अवलोकन मंत्री लखनलाल देवांगन ने किया।

शिविर में ग्रामीणों को अलग-अलग योजनाओं से लाभान्वित किया गया जिसमें हितग्राहियों को 100 दिन का रोजगार पूर्ण होने पर जॉब कार्ड, सात हितग्राहियों को केसीसी ऋण का चेक, ऋण पुस्तिका का वितरण, कृषि सिंचाई पंप, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत गैस कनेक्शन, मत्स्य पालन हेतु मछली जाल और आइस बॉक्स प्रदान किया गया।

संपादकीय

छापे में कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा

सरकार के कामकाज से ही जनता को पता चल जाता है कि सरकार कैसी है। सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो जनता को इस बात का पता पड़ने वालों छापों से चल जाता है। छापों से ही पता चल जाता है कि सरकार छापे मारने में कोई भेदभाव नहीं कर रही है। किसी को छोड़ा या बचाया नहीं जा रहा है। आम तौर पर माना जाता है जिस राजनीतिक दल की सरकार होती है उसके बड़े नेताओं का नेताओं के यहां भ्रष्टाचार के मामले में छापा नहीं मारा जाता है, उनको बचाने के सरकार के पास कई तरह के उपाय होते हैं। उन उपायों से राजनीतिक दल अपने बड़े नेताओं को सरकार के रहते बचा लेते हैं यानी सरकार ही खुद अपने नेताओं की रक्षा करनेवाली होती है। ऐसे नेताओं पर जब कोई कार्रवाई नहीं होती है तो जनता समझ जाती है कि यह सरकार अपने भ्रष्ट नेताओं व समर्थकों को बचाने वाली है।

राज्य में कांग्रेस की सरकार ऐसी ही सरकार मानी जाती है जो अपने नेताओं व समर्थकों को खुल कर बहती गंगा में हाथ धोने का मौका देती थी.जब सरकार खुद ही अपने नेताओं व समर्थकों को मौका देती है बहती गंगा में हाथ धोने को तो वह उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे कर सकती है। कांग्रेस के शासन का यह सूत्र तो जग जाहिर है कि हम खुद भी खाते हैं और अपने लोगों को खाने का मौका भी देते हैं। सब जानते हैं कांग्रेस के शासन में सब मिलजुलकर प्रेम से खाने में यकीन रखते हैं। यही वजह है कि जिस किसी राज्य में कांग्रेस का शासन जाता है तो पता चलता है कि पांच साल में सबने मिलजुलकर खूब खाया है। जिस तरह से भी खाने का मौका मिला है, खाने से कोई परहेज नहीं किया गया है। कोयला हो, सट्टा हो, शराब हो, कस्टम मिलिंग हो, डीएमएफ हो, भारतमाला परियोजना हो अब सामने आ रहा है कि लोगों ने कैसे मिलजुल कर प्रेम से खाया है।

साय सरकार ने तो सत्ता संभालते ही यह साफ कर दिया है कि सरकार किसी भी तरह का भ्रष्टाचार सहन नहीं करेगी । जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और जिनके बारे में जांच में पता चलेगा कि किसी तरह का भ्रष्टाचार किया गया है तो उसके खिलाफ भी कारर्वाई होगी। लोग समझ रहे थे कि हर सरकार जैसा करती है, साय सरकार भी वैसा करेगी। भ्रष्टाचार के मामले में अपने लोगों का नाम सामने कभी सामने आएगा तो वह बचाने का प्रयास करेंगी लेकिन साय सरकार ने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार के मामले में यदि किसी बड़े भाजपा नेता का नाम भी सामने आता है तो उसके खिलाफ एजेंसी वैसी ही कारर्वाई करेगी जैसे दूसरे दलों के नेताओं व समर्थकों के खिलाफ किया जाता है।

भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाला प्रकरण में कांग्रेस नेताओं समथर्कों के साथ ही भाजपा नेताओं व समर्थकों का नाम आने पर ईडी ने कोई भेदभाव नहीं किया कि भाजपा नेताओं के छापा न मारा जाए और कांग्रेस नेताओं के यहां ही छापा मारा जाए। कार्रवाई के दौरान पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के करीबी रिश्तेदार भूपेंद्र चंद्राकर और दुर्ग के भाजपा नेता चतुर्भुज राठी के ठिकानों पर छापेमारी की है ।कांग्रेस के समय तो ऐसा कभी सुना नहीं गया कि कांग्रेस नेताओं के यहां किसी भ्रष्टाचार के मामले में छापा मारा गया है लेकिन साय से समय लोग देख सुन व पढ़ रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में भाजपा नेताओं या उनके करीबियों के छापा मारा जा रहा है। इससे जनता में यह संदेश तो जाता है कि साय सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है और जो भी करेगा उसके खिलाफ बिना भेदभाव के कार्रवाई की जाएगी।

साय सरकार को जनता ने चुनाव में जिताकर सत्ता सौंपी तो उनके सामने यही सबसे बड़ी चुनौती थी उनकी सरकार पिछली सरकार से कैसे अलग हो सकती है। जनता को कैसे बताया जाए कि साय सरकार पिछली सरकार से कैसे अच्छी सरकार है। पिछली सरकार में जो कुछ हुआ उसे न होने देकर ही साय सरकार खुद की अलग ईमानदार सरकार की छबि बना सकती थी, पहचान बना सकती थी और दो साल में साय सरकार ऐसी छबि व पहचान बनाने में सफल रही है। भाजपा नेताओं का यहां ईडी का छापा पड़ने से यह साफ हो गया है कि साय सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है चाहे वह कांग्रेस नेता करे या भाजपा नेता करें, उनके खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई होगी।

पारिस्थितिकी बहाली का छत्तीसगढ़ मॉडल – 'बारनवापारा में काले हिरणों की वापसी'

धनंजय राठौर, संयुक्त संचालक, अशोक कुमार चन्द्रवंशी, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, रायपुर

मन की बात' से राष्ट्रीय क्षितिज तक का सफर- प्राय: सभी प्रकृति प्रेमियों का मानना है कि प्रकृति कभी भी अपना ऋण नहीं भूलती। यदि मनुष्य पूरी ईमानदारी से उसके संरक्षण की ओर एक कदम बढ़ाता है, तो प्रकृति उसे अपनी भव्यता से कई गुना वापस लौटाती है। छत्तीसगढ़ की पावन धरा, जो सदियों से अपनी नैसर्गिक संपदा और सघन वन क्षेत्रों के लिए विख्यात रही है, आज वन्यजीव संरक्षण के एक नए स्वर्णिम युग की ओर बढ़ रही है।

छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में स्थित बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य (लगभग 245 वर्ग किमी) में काले हिरणों (ब्लैकबक) का सफलतापूर्वक पुनरुद्धार हुआ है, जहाँ इनकी संख्या अब 200 के करीब पहुँच गई है। 1970 के दशक में विलुप्त हो चुके इन हिरणों को 2018 की पुनरुद्धार योजना और 2026 तक के वैज्ञानिक प्रयासों से वापस लाया गया। हाल ही में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में जब बारनवापारा अभ्यारण्य के काले हिरणों की सफल वापसी का उल्लेख किया, तो यह केवल एक राज्य की उपलब्धि नहीं रही, बल्कि भारत के पर्यावरण मानचित्र पर वन्यजीव संरक्षण का एक नया अध्याय बन गई।

विजन भरा नेतृत्व और प्रतिबद्धता- इस गौरवमयी उपलब्धि के सूत्रधार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं। उन्होंने इस सफलता को राज्य की समृद्ध जैव विविधता और पर्यावरण के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतिफल बताया है। मुख्यमंत्री श्री साय का मानना है कि प्रधानमंत्री की सराहना केवल एक प्रशंसा नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के वन विभाग और वहां के स्थानीय समुदायों के कठिन परिश्रम पर लगी राष्ट्रीय मुहर है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ आज विकास और पारिस्थितिकी तंत्र के बीच उस दुर्लभ संतुलन को साध रहा है, जिसकी आज पूरे विश्व को आवश्यकता है।

वैज्ञानिक रणनीतिः विलुप्ति से पुनर्वास तक- बारनवापारा अभ्यारण्य में काले हिरणों का दिखाई देना एक समय दुर्लभ हो गया था। लेकिन वन मंत्री केदार कश्यप के कुशल मार्गदर्शन और प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) अरुण कुमार पाण्डेय के रणनीतिक निर्देशन ने इस असंभव लक्ष्य को वास्तविकता में बदल दिया। फरवरी 2026 का महीना छत्तीसगढ़ के वन इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ, जब विशेषज्ञों की कड़ी निगरानी में 30 काले हिरणों को उनके प्राकृतिक आवास में 'सॉफ्ट रिलीज' पद्धति से मुक्त किया गया। यह प्रक्रिया केवल उन्हें जंगल में छोड़ने तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि वे नए वातावरण में बिना किसी तनाव के रच-बस सकें। ब्लैकबक कंजर्वेशन सेंटर में बेहतर पोषण और वैज्ञानिक देखभाल से इनकी संख्या में वृद्धि हुई।

प्रशासनिक इच्छाशक्ति और मैदानी संघर्ष- इस महाअभियान के पीछे उन जांबाज अधिकारियों और मैदानी अमले की मेहनत है, जिन्होंने दिन-रात एक कर दिया। मुख्य वन संरक्षक (रायपुर) श्रीमती सतोविशा समाजदार और वनमंडलाधिकारी (बलौदाबाजार) धम्मशील गणवीर के नेतृत्व में फील्ड स्टाफ, जीव वैज्ञानिकों और पशु चिकित्सकों की एक समर्पित टीम ने एक ढाल की तरह काम किया। वर्तमान में इन हिरणों की सुरक्षा के लिए हाई-टेक निगरानी प्रणाली, जीपीएस ट्रैकिंग और नियमित पेट्रोलिंग का उपयोग किया जा रहा है, जो छत्तीसगढ़ वन विभाग की तकनीकी दक्षता का प्रमाण है।

रामपुर ग्रासलैंडः- एक सुरक्षित भविष्य का पालना बारनवापारा अभ्यारण्य का यह मॉडल आज देश के अन्य राज्यों के लिए एक 'केस स्टडी' बन सकता है। यहाँ केवल काले हिरण की प्रजाति का पुनर्वास नहीं हुआ, बल्कि उनके लिए एक संपूर्ण आवास तंत्र विकसित किया गया। रामपुर ग्रासलैंड का वैज्ञानिक प्रबंधन, प्राकृतिक जल स्रोतों का जीणोद्धार और घास की स्थानीय प्रजातियों का संवर्धन वे मुख्य कारक हैं, जिन्होंने काले हिरणों को वहां फलने-फूलने के लिए प्रेरित किया। इसके अतिरिक्त, स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी ने मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व की एक अनूठी मिसाल पेश की है। काला हिरण (ब्लैकबक) भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला एक संकटग्रस्त मृग है। नर काले हिरण का रंग गहरा भूरा से काला होता है, उसके लंबे सर्पिलाकार सींग होते हैं और शरीर का निचला भाग सफेद होता है। मादा काले हिरण हल्के भूरे रंग की होती हैं और सामान्यतः उनके सींग नहीं होते। यह प्रजाति खुले घास के मैदानों में पाई जाती है और दिन के समय सक्रिय रहती है। इसका मुख्य आहार घास और छोटे पौधे होते हैं। इनकी ऊंचाई लगभग 74 से 84 सेंटीमीटर होती है। नर का वजन 20 से 57 किलोग्राम के बीच और मादाओं का 20 से 33 किलोग्राम तक होता है। नर काले हिरण की सर्पिलाकार सींगें, जो लगभग 75 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती हैं, इन्हें आसानी से पहचानने योग्य बनाती हैं।

भविष्य की राह और राष्ट्रीय संदेश- बारनवापारा अभ्यारण्य में गूंजती काले हिरणों की चहल-कदमी और उनकी कुलाचें इस बात का जीवंत साक्ष्य हैं कि यदि इंसान प्रकृति के प्रति अपनी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी समझ ले, तो खोई हुई धरोहर को फिर से लौटाया जा सकता है। यह पहल आने वाली पीढ़ियों के लिए एक 'लिविंग लैबोरेटरी' (जीवंत प्रयोगशाला) के रूप में कार्य करेगी, जहाँ वे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना सीख सकेंगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'मन की बात' ने हमारे नवाचारों को एक वैश्विक मंच प्रदान किया है। छत्तीसगढ़ सरकार पर्यावरण संवर्धन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जोड़कर एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रही है, जहाँ मनुष्य और वन्यजीव दोनों सुरक्षित हों।आज जब हम बारनवापारा अभ्यारण्य की खुली वादियों में कुलाचें भरते काले हिरणों को देखते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति स्वयं मुस्कुराते हुए छत्तीसगढ़ के इस सराहनीय प्रयास को अपना आशीर्वाद दे रही है। यह छत्तीसगढ़ के गौरव का वह उत्कर्ष है, जिसकी चमक अब पूरे देश को प्रेरित कर रही है।

आधी दुनिया : घर-बाहर के दबाव में तनाव झेलती महिलाएं

दीपिका अरोरा

शोध के मुताबिक़, 72.2 प्रतिशत कामकाजी महिलाएं उच्च तनाव में हैं, जो पुरुषों (53.64 प्रतिशत) से काफी अधिक है। 90 प्रतिशत महिलाएं यद्यपि मानती हैं कि स्वास्थ्य मुद्दे उनकी उत्पादकता को प्रभावित करते हैं, तथापि भारतीय समाज की रूढ़िवादी सोच के कारण वे मदद मांगने से झिझकती हैं।

मल्टीटॉस्किंग एक नैसर्गिक गुण है, महिलाएं जिसमें विशेष रूप से माहिर मानी गई हैं। यूं भी अधिकतर भारतीय परिवारों में घरेलू कार्य स्त्रियों के ही हवाले रहते हैं, भले ही वह अतिरिक्त भार उठाने में सक्षम हो अथवा न। परंपरागत समाज के लिए यह आम बात हो सकती है किंतु परिवर्तित परिदृश्य में दोहरे दायित्व का निर्वहन कहीं न कहीं नारी-स्वास्थ्य पर भारी पड़ रहा है। हेल्थ स्टार्टअप त्राया द्वारा भारत के 15 राज्यों की 5,35,373 महिलाओं पर किया नवीनतम सर्वेक्षण देश में लगभग 50 प्रतिशत महिलाओं के प्रतिदिन क्रॉनिक स्ट्रेस झेलने का खुलासा करता है। पश्चिम बंगाल में 52.2 प्रतिशत महिलाएं तनाव की शिकार हैं, तमिलनाडु एवं दिल्ली में यह आंकड़ा क्रमशः 50.5 तथा 47.8 प्रतिशत है। सर्वाधिक चिंताजनक है, तनाव की कोई आकस्मिक घटना न होकर निरंतर चलने वाली समस्या बनना, जो कि नींद से लेकर महिलाओं के हामीनल स्वास्थ्य तक को चपेट में ले रही है।

सर्वे के निष्कर्ष बताते हैं कि कार्य तथा व्यक्तिगत जीवन में असंतुलन, कार्यस्थल पर होने वाला भेदभाव, आर्थिक दबाव तथा सामाजिक अपेक्षाओं के फलस्वरूप उपजते तनाव से महिलाओं की मूलभूत आवश्यकताएं बहुतेरे प्रभावित हो रही हैं। लगभग 5 में से 2 महिलाएं पर्याप्त निद्रा नहीं ले पा रहीं, वहीं हर 2 में से 1 महिला पेट तथा पाचन संबंधी समस्याओं से जूझ रही है। रिपोर्ट के अनुसार, असल में ये सभी दिक्कतें अलग-अलग न होकर परस्पर जुड़ी हुई हैं। कुल मिलाकर यह उसी तनाव के परिणाम हैं, जिसे महिलाएं नित्यप्रति ढो रही हैं।

विशेषज्ञों की मानें तो, पारिवारिक-सामाजिक भूमिका के तहत महिलाओं से अत्यधिक अपेक्षाएं रखने वाली पारंपरिक सोच तथा आधुनिक जीवनशैली के आपसी द्वंद्व ने समस्या और गहरा दी है। शोध के मुताबिक़, 72.2 प्रतिशत कामकाजी महिलाएं उच्च तनाव में हैं, जो पुरुषों (53.64 प्रतिशत) से काफी अधिक है। 90 प्रतिशत महिलाएं यद्यपि मानती हैं कि स्वास्थ्य मुद्दे उनकी उत्पादकता को प्रभावित करते हैं, तथापि भारतीय समाज की रूढ़िवादी सोच के कारण वे मदद मांगने से झिझकती हैं। इसका एक बड़ा कारण आज भी व्यापक स्तर पर व्याप्त लिंगभेद है।

सर्वे यह भी बताता है कि महिलाओं से लगातार ज़्यादा काम की उम्मीद पालने वाली संकीर्ण सोच में यह कम ही पूछा जाता है कि क्या उनके पास इसे निभाने के लिए जरूरी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बची भी है या नहीं? घर-कार्यस्थल में सामंजस्य बिठाने का प्रयास एवं प्रत्येक कार्यक्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन की चाह तनाव के रूप में उभरकर उदासी, अवसाद, चिड़चिड़ेपन आदि अनेकानेक व्याधियों की उत्पत्ति का निमित्त बन रही है।

दुर्भाग्य से आज भी भारतीय समाज में मानसिक रोगों को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जाता। महिलाओं के संदर्भ में तो स्थिति विशेषकर निराशाजनक है। उनके स्वास्थ्य के प्रति पारिवारिक दायित्व अथवा सामाजिक जागरूकता के बारे तथ्य खंगालें तो सर्वे के मुताबिक़, अधिकांश मामलों में महिलाओं की भावनाओं एवं उनके मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिस कारण तनाव, चिंता गहरे अवसाद में परिणत होने लगते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्थिति और भी जटिल है। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, साक्षरता का अभाव, निर्धनता तथा अंधविश्वासी प्रवृत्ति के चलते मानसिक रोगों को भूत-प्रेत की छाया अथवा जादूझटोने का प्रभाव मान लिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में डॉक्टरी मदद लेने की बजाय ओझा, तांत्रिक या झाड़-फूंक करने वालों को तरजीह दी जाती है, जो महिलाओं की हालत को और बिगाड़ देते हैं। कई मामलों में मौत तक हो जाती है।

अपनी सेहत की अनदेखी करने में महिलाएं भी कम दोषी नहीं। आमतौर पर स्त्रीवर्ग अपना ध्यान रखने अथवा क्षमता के अनुरूप कार्य करने की बजाय दूसरों की जरूरतों को अधिक अधिमान देता है। सबका ख़्याल रखना निस्संदेह, एक सराहनीय गुण है, किंतु कर्तव्य-पालन के अतिरेक में यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि सबका शब्द में महिलाएं खुद भी शामिल हैं। तनाव ढोती महिलाओं की चुप्पी कालांतर में स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है। इससे पूर्व कि तनाव जीवन को अस्त-व्यस्त कर डाले, काउंसलिंग करना अनिवार्य हो जाता है।

असल में, नर-नारी, परिवार तथा समाज रूपी गाड़ी चलाने वाले दो पहिए हैं। किसी भी पहिए पर क्षमता से अधिक बोझ लादना उसे क्षतिग्रस्त बना छोड़ेगा। देश की आधी आबादी का स्थाई तौर पर तनाव से जूझना मात्र स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा न होकर समग्र रूप में एक बहुआयामी सामाजिक समस्या है। मानवीय आधार पर समझना होगा कि महिलाओं की भावनात्मक जरूरतें भी पुरुषों जितनी ही महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें अनदेखा करना सरासर अन्याय है।

डॉक्टरों के कथनानुसार, दीघर्कालीन तनाव के प्रति बरती गई कोताही भविष्य में असाध्य रोग बन सकती है। भीतर ही भीतर घुटने की अपेक्षा क्यों न परिजनों को शिष्टतापूर्वक अपनी मनोस्थिति से अवगत करवाया जाए ताकि समय रहते समुचित समाधान मिल सके? इसके लिए समाज, परिवार तथा सरकार को मिलकर एक ऐसा माहौल सृजित करना होगा, जहां महिलाएं निःसंकोच अपनी समस्याएं साझा कर सकें। मिल-बांटकर काम करने से जहां कायर्भार घटेगा, वहीं रिश्तों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी; तनावरहित नारी अधिक आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी तथा स्वस्थ जीवन जी पाएगी।

जहां था पुरुषों का दबदबा, वहां अब महिलाओं ने जमाया अपना सिक्का, टीम प्रहरी ने बदली रायपुर के सड़कों की तस्वीर, मुख्यमंत्री साय ने की थी इनकी सराहना

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

रायपुर में सड़कों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अब केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रह गई है, बल्कि यह साहस, धैर्य और बदलाव की एक ऐसी कहानी बन गई है, जिसे ह्यटीम प्रहरीह्न की महिलाएं हर दिन जी रही हैं। करीब एक साल पहले शुरू हुई इस पहल में 20 महिलाओं को शामिल किया गया था, जिनकी जिम्मेदारी थी कि कार्रवाई के दौरान महिलाओं से जुड़े मामलों को संभाला जाए, लेकिन धीरे-धीरे इन महिलाओं ने अपनी भूमिका को सीमित दायरे से बाहर निकालकर पूरे ऑपरेशन का अहम चेहरा बना दिया। आज ये महिलाएं न सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में बराबरी से हिस्सा ले रही हैं, बल्कि कई बार सबसे आगे खड़े होकर हालात को नियंत्रित भी करती हैं।

इन महिलाओं के लिए यह सफर आसान नहीं रहा। शुरुआत में परिवार और समाज दोनों की ओर से कई तरह के सवाल खड़े किए गए। यह कहा गया कि यह काम जोखिम भरा है, लड़कियों के लिए ठीक नहीं है, शादी और बच्चों की जिम्मेदारियों पर असर पड़ेगा। लेकिन इन सब आशंकाओं के बावजूद महिलाओं ने पीछे हटने के बजाय इस चुनौती को स्वीकार किया। आज हालात बदल चुके हैं। जो परिवार पहले चिंतित थे, अब वही गर्व महसूस करते हैं कि उनकी बेटियां शहर की व्यवस्था को बेहतर बनाने में भूमिका निभा रही हैं। टीम की सदस्य श्रीमती संतोषी सोनी कहती हैं कि अब वे काम करते समय महिला या पुरुष के रूप में नहीं सोचतीं, बल्कि एक जिम्मेदार कमर्चारी के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाती हैं।

मैदान में उतरने के बाद इन महिलाओं को हर दिन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अक्क्र्टर के पास सांभर-बड़ा के एक ठेले को हटाने की कार्रवाई के दौरान एक महिला ने टीम को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। माहौल तनावपूर्ण हो गया, लेकिन टीम की सदस्य श्रीमती बिंदिया ने संयम नहीं खोया और स्थिति को संभाल लिया। इसी तरह पचपेड़ी नाका में कार्रवाई के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि अपशब्द कहने पर ऋक्रफदर्ज करानी पड़ी। कई बार ऐसी स्थिति बनती है जब लोग कार्रवाई को व्यक्तिगत तौर पर लेने लगते हैं, क्योंकि टीम के सामने वही महिलाएं खड़ी दिखाई देती हैं, जिनसे उनका सीधा सामना होता है। ऐसे में प्रभावितों का गुस्सा सबसे पहले इन्हीं महिलाओं पर निकलता है।

हालात कई बार और भी गंभीर हो जाते हैं। समता कॉलोनी में कार्रवाई के दौरान पथराव की घटना हुई, जहां टीम को खुद को बचाते हुए काम जारी रखना पड़ा। वहीं काठाडीह में प्रधानमंत्री आवास योजना की जमीन पर कब्जा हटाने के दौरान सामने से हथियार तक निकाल लिए गए। इन घटनाओं ने यह साफ कर दिया कि यह काम जोखिम भरा है, मगर प्रशासनिक दायित्व को पूरा कर रही इन महिलाओं ने हमेशा शासकीय अमले के सहारे पर भरोसा किया। टीम की महिलाएं बताती हैं कि अब उन्हें अनुभव के आधार पर यह समझ आने लगा है कि कब सामने वाला पक्ष आक्रामक हो सकता है और कब स्थिति को समझाइश से संभाला जा सकता है। उनके मुताबिक, कई बार सख्ती जरूरी हो जाती है, तो कई बार बातचीत ही सबसे प्रभावी तरीका साबित होती है।

खमतराई जोन में एक कपड़ा दुकान के बाहर विवाद बढ़ा, तो महिलाओं ने खुद आगे बढ़कर एक युवक को घेरकर समझाया और स्थिति को बिगड़ने से रोका। कई बार ऐसा भी हुआ कि महिलाओं की मौजूदगी के बावजूद पुरुष आक्रामक हो गए और स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई। ऐसे समय में टीम को मजबूती से खड़ा रहना पड़ता है और जरूरत पड़ने पर सख्ती भी करनी पड़ती है। कुछ मामलों में तो हालात ऐसे बने कि लोगों को जबरन वाहन में बैठाकर हटाना पड़ा। इसके बावजूद टीम ने हर बार यह कोशिश की कि स्थिति नियंत्रण में रहे और किसी तरह का बड़ा विवाद न हो। इन महिलाओं को सिटी कोतवाली में विशेष प्रशिक्षण दिया गया है, जिसने उन्हें न केवल सख्त बनाया है, बल्कि संवेदनशील भी रखा है। यही वजह है कि कार्रवाई के दौरान जब ठेला या गुमटी हटाई जाती है और लोग भावुक होकर रोने लगते हैं, तो यही महिलाएं उन्हें समझाती हैं कि उनका सामान सुरक्षित रहेगा और वे उसे बाद में ले सकते हैं। इस तरह सख्ती और संवेदनशीलता का संतुलन बनाए रखना इनके काम की सबसे बड़ी खासियत बन गया है। टीम की सदस्य बताती हैं कि उनका उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि शहर की व्यवस्था को बेहतर बनाना है। कार्रवाई के दौरान कई बार दबाव और लालच भी सामने आते हैं। पैसे देने के प्रस्ताव, पहचान का हवाला और सिफारिशें—यह सब इस काम का हिस्सा हैं, लेकिन टीम ने शुरू से ही यह तय कर लिया है कि किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। यही ईमानदारी उनकी पहचान बनती जा रही है और लोगों के बीच उनके प्रति भरोसा भी बढ़ा रही है। शुरुआत में इस पहल को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया मिली-जुली थी। कई लोग इसे सख्ती के रूप में देखते थे और नाराजगी जताते थे, लेकिन समय के साथ तस्वीर बदलने लगी है। अब सड़कों के चौड़े होने और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार को लोग महसूस कर रहे हैं। नगर निगम पहले भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करता रहा है, लेकिन महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बाद उसका असर ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। लोग अब यह समझने लगे हैं कि सड़क पर किया गया अतिक्रमण केवल जगह घेरने का मामला नहीं है, बल्कि इससे दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ता है। टीम की सदस्य पिंकी बताती हैं कि शुरुआत में परिचित लोग भी ताने देते थे और उनके काम को लेकर सवाल उठाते थे। लेकिन अब वही लोग समझ रहे हैं कि यह काम क्यों जरूरी है। समाज में इस बदलाव को महिलाएं अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानती हैं। उनके लिए यह केवल नौकरी नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है, जिसके जरिए वे शहर को बेहतर बना रही हैं। आज हालात यह हैं कि टीम प्रहरी की इस पहल को हर स्तर पर सराहना मिल रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से लेकर महापौर श्रीमती मीनल चौबे तक इस टीम के काम की तारीफ कर चुके हैं। लेकिन इन महिलाओं को असली संतोष तब मिलता है, जब वे सड़कों को साफ और व्यवस्थित देखती हैं और लोगों को सुरक्षित चलते हुए पाती हैं। टीम प्रहरी में इन महिलाओं की है अहम भूमिका –श्रीमती कविता नायक, कु. कहकशां परवीन, श्रीमती कांता निहाल, श्रीमती सुकांति सिक्का, श्रीमती बिंदिया नाग, श्रीमती विमला ताण्डी, श्रीमती मंजु आमदे, श्रीमती पिंकी निहाल, श्रीमती रोमा मेरी अरोरा, श्रीमती कल्पना बघेल, श्रीमती गौरी साहू, श्रीमती गौतमा मेश्राम, श्रीमती डॉली भिवंडे, श्रीमती पूर्णिमा बघेल, श्रीमती छुनकी हरपाल, कु. तुलिका कौशल, कु. ममता भिवंडे, श्रीमती लता ताण्डी, श्रीमती समीमा बेगम तथा श्रीमती संतोषी सोनी। 'टीम प्रहरी' की महिला टीम आज सिर्फ कार्रवाई का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि बदलाव की अग्रिम पंक्ति में खड़ी वो महिलाएं हैं, जो हर दिन यह साबित कर रही हैं कि हिम्मत और जिम्मेदारी के सामने कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती।

दूरगामी परिणाम झेलने तैयार रहना चाहिए

आरबीआई ने जो कहा है, उसका सार है कि पश्चिम एशिया में युद्ध से सप्लाई शृंखला बाधित हो गई है, जिसके दूरगामी परिणाम झेलने के लिए सबको तैयार रहना चाहिए। बैंक ने आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटा दिया है।

महंगाई की तगड़ी मार फिर आ पड़ी है, जबकि अर्थव्यवस्था के सारे गुलाबी अनुमान गड़बड़ाते दिख रहे हैं- भारतीय रिजर्व बैंक ने जो कहा है, उसका यही सार है। संदेश यह है कि पश्चिम एशिया में युद्ध ने सप्लाई शृंखला को बाधित रखा दिया है, जिसके दूरगामी परिणाम झेलने के लिए सबको तैयार हो जाना चाहिए। बुधवार को अपनी मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान को 6.9 से घटा कर 6.7 प्रतिशत कर दिया, जबकि मुद्रास्फीति दर के पांच प्रतिशत तक पहुंचने की आशंका जता दी। इसके अलावा आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने अर्थव्यवस्था पर मंडरा रहे पांच जोखिमों का जिक्र किया।

इनके मुताबिक होरमुज जलमार्ग में आई रुकावट के कारण कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, उर्वरक आदि की उपलब्धता प्रभावित हो रही है, जिसका असर घरेलू उत्पादन पर पड़ेगा। खाड़ी क्षेत्र के प्रभावित होने की वजह से मालवाही जहाजों को लंबे समुद्री रूट लेने पर पड़ रहे हैं, जिससे माल भाड़े और माल डिलिवरी के समय में इजाफा हुआ है। मल्होत्रा ने चेताया कि जो शुरुआत में जिसे आपूर्ति झटका समझा गया है, मध्यम अवधि में वह मांग झटके में तब्दील हो सकता है। आपूर्ति बाधा से चीजें महंगी होंगी, जिससे बाजार में उनकी मांग घटेगी।

दरअसल, एमएमसीजी कंपनियों की मार्च की रिपोर्ट से संकेत मिला है कि असल महंगाई रिजर्व बैंक के अनुमान से भी ज्यादा बढ? वाली है। इसके मुताबिक कच्चे तेल और अन्य इनपुट सामग्रियों की लागत में बढ़ोतरी के कारण इन कंपनियों ने मार्च में अपने उत्पादों की कीमत 7 से 8 फीसदी तक बढ़ा दी। जानकारों के मुताबिक वैश्विक तनाव जारी रहा, तो आने वाले महीनों में कीमतें 10 से 15 प्रतिशत तक और बढ़ सकती हैं। साथ ही रिजर्व बैंक ने आगाह किया है कि उर्वरकों की कमी का असर कृषि पैदावार पर पड़ेगा, जिससे खाद्य संकट खड़ा हो सकता है। आयात महंगा होने और पूंजी के बाहर जाने के कारण रुपया पहले से झटके खा रहा है। यानी संकट गहरा है, जिसका कोई समाधान सरकार के पास नहीं है।

एनएचएआई और भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने किया प्रिसीजन पोजिशनिंग पर कार्यशाला का आयोजन

सीओआरएस तकनीक से राजमार्ग निर्माण में आएगी तेजी, सेंटीमीटर की सटीकता के साथ होगा डिजिटल सर्वे

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में सीओआरएस नेटवर्क के माध्यम से प्रिसीजन पोजिशनिंग सेवाएं विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक जीपीएस प्रणालियों की सीमाओं को पार कर अत्याधुनिक सीओआरएस तकनीक को अपनाना है, ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की योजना और निर्माण को बेहतर बनाया जा सके।

एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी प्रदीप कुमार लाल ने कार्यशाला के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राजमार्ग निर्माण अब और भी स्मार्ट व आधुनिक होने जा रहा है। सीओआरएस तकनीक को अपनाने से हम बुनियादी ढांचे के विकास में वैश्विक मानकों को छू सकेंगे। यह तकनीक न केवल सर्वेक्षण प्रक्रिया को तेज करेगी, बल्कि ठेकेदारों और इंजीनियरों को रियल-टाइम डॉटा उपलब्ध कराकर निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करेगी।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अधीक्षण सर्वेक्षक और छत्तीसगढ़ के प्रभारी राजेश रंजन ने तकनीकी सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि सीओआरएस नेटवर्क एक ऐसी आधुनिक बुनियादी ढांचा प्रणाली है जो पूरे देश में सटीक स्थान की जानकारी प्रदान करती है। राजमार्ग क्षेत्र में इसके उपयोग से जटिल भौगोलिक क्षेत्रों में भी त्रुटिहीन डिजिटल मैपिंग और डॉटा संग्रहण संभव हो पाएगा।

कार्यशाला में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के ऑफिसियल सर्वेयर प्रभात कुमार प्रधान ने बताया कि सीओआरएस तकनीक के माध्यम से राजमार्गों के सर्वेक्षण और निर्माण कार्यों में सेंटीमीटर-स्तर की सटीकता प्राप्त की जा सकती है। यह तकनीक न केवल रियल-टाइम मॉनिटरिंग में सहायक है, बल्कि इससे निर्माण की गुणवत्ता में सुधार होगा और परियोजनाओं के समय व लागत में भी भारी बचत होगी। एनएचएआई के परियोजना निदेशक डी.डी. पालीवार, दिग्विजय सिंह और मुकेश कुमार तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के एजीएक्यूटिव इंजीनियर रामवीर यादव सहित अनेक अधिकारी-कर्मचारी भी कार्यशाला में उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री साय ने अविस्मरणीय यात्रा पुस्तक का किया विमोचन

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में पत्रकार श्रीमती नीरा साहू द्वारा गुजरात यात्रा पर लिखी गई पुस्तक अविस्मरणीय यात्रा का विमोचन किया। इस अवसर पर श्री साय ने श्रीमती साहू को उनकी उत्कृष्ट रचना के लिए बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिला पत्रकारों ने मुख्यमंत्री का अभिनंदन करते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में विधानसभा में आयोजित विशेष सत्र एवं शासकीय संकल्प के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने इसे महिलाओं के सम्मान, सशक्तिकरण और अधिकारों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल बताया, जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने महिला पत्रकारों के अध्ययन भ्रमण की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक भ्रमण पत्रकारों की दृष्टि को व्यापक बनाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह यात्रा-वृत्तांत पर्यटन प्रेमियों के लिए एक उपयोगी मार्गदर्शिका सिद्ध होगा। इस अवसर पर सुश्री निशा द्विवेदी, सुश्री चित्रा पटेल, सुश्री लवलीना शर्मा, जनसंपर्क विभाग की उप संचालक डॉ. दानेश्वरी सोंधाकर, सहायक संचालक सुश्री संगीता लकड़ा एवं सुश्री आमना खातून सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित थे।

श्रमिक समाज की आधारशिला हैं और उनके बिना विकास की कल्पना अधूरी : देवांगन

रायपुर। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस (मई दिवस) के अवसर पर प्रदेश के श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने राज्य के श्रमिकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सभी मेहनतकश श्रमिकों के सुखमय और उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि 1 मई का दिन श्रमिकों के परिश्रम, समर्पण और योगदान के प्रति आभार व्यक्त करने का विशेष अवसर है। मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि श्रमिक समाज की आधारशिला हैं और उनके बिना विकास की कल्पना अधूरी है। उन्होंने श्रमिकों की सामाजिक और आर्थिक खुशहाली के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार श्रमिकों सहित सभी जरूरतमंद वर्गों के समग्र विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों और उनके परिवारों को विभिन्न योजनाओं का लाभ तेजी से उपलब्ध कराया जा रहा है। श्रम विभाग के अंतर्गत संचालित तीनों मंडलों- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल, संगठित कर्मकार मंडल और राज्य सामाजिक सुरक्षा एवं श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है।

हेलमेट बैंक : सड़क सुरक्षा की दिशा में एक सार्थक पहल

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

सड़क दुर्घटनाओं में लगातार हो रही वृद्धि आज एक गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है। विशेष रूप से दोपहिया वाहन चालकों में हेलमेट के उपयोग की कमी के कारण दुर्घटनाओं में मृत्यु और गंभीर चोटों के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसी चुनौती से निपटने के लिए जिला प्रशासन कोण्डागांव द्वारा एक अभिनव पहल करते हुए हेलमेट बैंक की शुरुआत की गई है। यह पहल न केवल लोगों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित कर रही है, बल्कि सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

हेलमेट बैंक योजना का मुख्य उद्देश्य दोपहिया वाहन चालकों में हेलमेट पहनने की आदत विकसित करना और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर एवं गंभीर चोटों को कम करना है। इस योजना के अंतर्गत नेशनल हाईवे 30 के आसपास स्थित उन ग्राम पंचायतों में हेलमेट बैंक स्थापित किए गए हैं, जहां दुर्घटनाओं की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। वर्तमान में जिले के 9 ग्राम पंचायत— मस्सुकोकोड़ा, माझीआंठगांव, लंजोडा, अनंतपुर, बड़ेराजपुर, बनियागांव, मसोरा, मर्दापाल और माकड़ी में यह व्यवस्था संचालित की जा रही है।

इन हेलमेट बैंकों में 120 से अधिक हेलमेट उपलब्ध कराए गए हैं और अब तक 400 से ज्यादा लोग इस सुविधा का लाभ उठा चुके हैं। योजना के तहत बिना हेलमेट यात्रा कर रहे दोपहिया वाहन चालकों को अस्थायी रूप से हेलमेट उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वे सुरक्षित यात्रा कर सकें। यह व्यवस्था विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी साबित हो रही है, जो किसी कारणवश हेलमेट साथ नहीं रख पाते। हेलमेट प्राप्त करने की प्रक्रिया भी सरल और सुविधाजनक रखी गई है। इच्छुक व्यक्ति को अपना पहचान पत्र या नाममात्र की राशि जमा करनी होती है। उपयोग के बाद हेलमेट को वापस हेलमेट बैंक में जमा करना अनिवार्य होता है, जिससे अन्य लोग भी इसका लाभ ले सकें।

कलेक्टर ने इस पहल के माध्यम से नागरिकों से अपील की है कि वे हेलमेट पहनने को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। उन्होंने कहा कि परिवार के सदस्य भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं— जब भी कोई व्यक्ति दोपहिया वाहन से बाहर जाए, उसे हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करें। छोटी-सी सावधानी बड़े हादसों से बचा सकती है। स्थानीय नागरिकों ने भी इस पहल की सराहना की है और इसे सड़क सुरक्षा की दिशा में एक सकारात्मक एवं प्रभावी कदम बताया है। हेलमेट बैंक जैसी पहलें न केवल जीवन बचाने का माध्यम बनती हैं, बल्कि समाज में जिम्मेदारी और जागरूकता का संदेश भी देती हैं।

132 केव्ही उपकेन्द्र छुरीखुर्द में 40 एमव्हीए का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर उर्जीकृत, उपभोक्ताओं को निर्बाध होगी बिजली आपूर्ति

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुये ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विद्यमान उपकेन्द्रों में स्थापित पॉवर ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है। इसी क्रम में 132 केव्ही उपकेन्द्र कोरबा जिले के छुरीखुर्द में 4 करोड़ 31 लाख रूपये की लागत से 40 एम.व्ही.ए. क्षमता का अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है।

विद्युत कंपनी के विशेष प्रयासों से विद्युत विकास के लिए स्वीकृत इस कार्य से उपकेन्द्र के परिधि में आने वाले उपभोक्ताओं को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा अब उन्हे उच्च गुणवत्तापूर्ण तथा निर्बाध विद्युत की आपूर्ति होगी।

ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध निदेशक आर.के.शुक्ला ने स्वीच का बटन ऑन कर नये ट्रांसफार्मर के माध्यम से विद्युत सप्लाई प्रारंभ की तथा उन्होने अपने उद्बोधन में कहा कि विद्युत विभाग उपभोक्ताओं की सुविधाओं में निरंतर वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कडी में इस उपकेन्द्र में अतिरिक्त 40 एमव्हीए क्षमता के पॉवर ट्रांसफार्मर को उर्जीकृत किया गया है, जिसका लाभ इस क्षेत्र के 50 गांवों के उपभोक्ताओं को मिलेगा।

मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय की संवेदनशील पहल

नई दृष्टिबिंदु / जशपुर

मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय की संवेदनशील एवं त्वरित पहल के परिणामस्वरूप जशपुर जिले के विकासखंड फरसाबहार अंतर्गत ग्राम पगुराबहार(सराईटोली) निवासी अमित राम का पार्थिव शरीर केरल के कोझिकोड से उनके गृह ग्राम सुरक्षित रूप से पहुंचाया गया।

अमित राम केरल के कोझिकोड में ट्रेन से यात्रा के दौरान दुर्घटनावश ट्रेन से नीचे गिरने की वजह से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। घटना के पश्चात शोकाकुल परिजनों ने पार्थिव शरीर को उनके गृह ग्राम लाने के लिए मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से सहायता हेतु निवेदन किया था।

मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल आवश्यक समन्वय स्थापित किया। इसके परिणामस्वरूप अमित राम के पार्थिव शरीर को विमान के माध्यम से केरल से रांची तक लाया गया। इसके पश्चात मुकांजली वाहन के जरिए उन्हें उनके गृह ग्राम पगुराबहार (सराईटोली) पहुंचाया गया। किसी प्रियजन की असमय मृत्यु परिवार के लिए अत्यंत पीड़ादायक होती है, विशेषकर जब यह घटना घर से दूर घटित हो। ऐसे समय में पार्थिव शरीर को शीघ्र घर लाना परिजनों की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय द्वारा की गई इस त्वरित एवं मानवीय पहल ने शोकाकुल परिवार को बड़ी राहत और मानसिक संबल प्रदान किया है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की यह पहल उनकी संवेदनशीलता और जनसेवा के प्रति समर्पण को दर्शाती है। वे केवल एक जनप्रतिनिधि ही नहीं, बल्कि एक अभिभावक की तरह प्रदेशवासियों के सुख-दुःख में सदैव सहभागी रहते हैं। प्रदेश का कोई भी नागरिक संकट में हो, मुख्यमंत्री उसकी पीड़ा को समझते हुए हर संभव सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। इस कठिन समय में मिली सहायता के लिए मृतक के परिजनों ने मुख्यमंत्री एवं कैंप कार्यालय के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया है।

भीषण गर्मी में वन्यजीवों के लिए 'संजीवनी' बना बारनवापारा

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन और जैव-विविधता के केंद्र बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य ने इस भीषण गर्मी में वन्यजीव संरक्षण की एक नई इबारत लिखी है। जब पारा आसमान छू रहा है और प्राकृतिक जल स्रोत सूखने की कगार पर हैं, तब बलौदाबाजार वनमंडल द्वारा अपनाई गई वैज्ञानिक और व्यावहारिक जल प्रबंधन प्रणाली वन्यजीवों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है।

हर 5 वर्ग किलोमीटर पर पानी की उपलब्धता

अभयारण्य प्रबंधन ने पूरे क्षेत्र का विस्तृत मानचित्रण कर 240 से अधिक जल स्रोतों को चिन्हित किया है। इसमें तालाब, स्टॉप डैम, वॉटरहोल और कृत्रिम सॉसर शामिल हैं।

रणनीति ऐसी बनाई गई है कि वन्यप्राणियों को पानी के लिए भटकना न पड़े। प्रत्येक 5 वर्ग किलोमीटर के दायरे में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

बारनवापारा का यह मॉडल केवल पानी भरने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह डेटा और तकनीक पर आधारित है। स्थलों का नियमित निगरानी का प्रबंध किया गया है। प्रत्येक 15 दिनों में जल स्तर का आकलन किया जाता है। 'स्टाफ गेज' के माध्यम से जल स्तर मापकर स्रोतों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है, ताकि जहां पानी कम हो, वहां तुरंत कार्रवाई की जा सके। सभी जल स्रोतों की जियो-टैगिंग की गई है, जिससे मुख्यालय से भी इनकी स्थिति पर सटीक नजर रखी जा सके।

पानी की पीएच और टीडीएस की नियमित जांच

वन्यजीवों को केवल पानी ही नहीं, बल्कि 'सुरक्षित पानी' मिले, इसके लिए नियमित अंतराल पर पीएच मान और टीडीएस का परीक्षण किया जा रहा है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि पानी वन्यजीवों के स्वास्थ्य के अनुकूल हो। जिन दुर्गम क्षेत्रों में प्राकृतिक जल स्रोत सूख गए हैं, वहां विभाग द्वारा टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है।

मिनरल्स का भी रखा ख्याल : स्थापित किए 'साल्ट लिक'

वन्यजीवों के समग्र स्वास्थ्य और उनकी खनिज आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जल स्रोतों के पास रणनीतिक रूप से 'साल्ट लिक' बनाए गए हैं। इससे जानवरों को पानी के साथ-साथ आवश्यक मिनरल्स भी एक ही स्थान पर मिल रहे हैं, जो गर्मी के तनाव को कम करने में सहायक है।

वनमंडलाधिकारी ने कहा कि एक ऐसी जवाबदेह प्रणाली विकसित की है जो केवल तात्कालिक राहत नहीं, बल्कि दीर्घकालिक समाधान प्रदान करती है। लगातार निगरानी और वैज्ञानिक डेटा के कारण हम जल स्तर गिरने से पहले ही वैकल्पिक व्यवस्था करने में सक्षम हैं। यह मॉडल भविष्य के वन्यजीव प्रबंधन के लिए एक मानक स्थापित कर रहा है।"

पोट्टु लईका पहलह्व से बदली तस्वीर- कुपोषण पर प्रभावी प्रहार, स्वस्थ बचपन की ओर सशक्त कदम

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

छत्तीसगढ़ में कुपोषण के विरुद्ध चल रही मुहिम अब प्रभावी परिणामों के साथ एक मजबूत जन-आंदोलन का रूप लेती दिख रही है। राजनांदगांव जिले में प्रशासन के नेतृत्व में महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के समन्वित प्रयासों से संचालित पोट्टु लईका पहल अभियान ने बच्चों के पोषण स्तर में उल्लेखनीय सुधार दर्ज कराते हुए राज्य के लिए एक प्रेरणादायक मॉडल प्रस्तुत किया है।

जून 2025 से प्रारंभ इस अभिनव अभियान का उद्देश्य केवल कुपोषण की पहचान करना नहीं, बल्कि समुदाय को जागरूक कर व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से स्थायी समाधान सुनिश्चित करना है। इसी कड़ी में प्रत्येक गुरुवार को जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में पालक चौपाल का नियमित आयोजन किया जा रहा है, जहां अभिभावकों को तिरंगा भोजन (संतुलित और विविध आहार), शिशु एवं मातृ पोषण, स्तनपान के महत्व, एनीमिया की रोकथाम, स्वच्छता और बच्चों की समुचित देखभाल जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सरल, व्यवहारिक और स्थानीय भाषा में जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही कुपोषित बच्चों की नियमित जांच, वजन-लंबाई की मॉनिटरिंग, आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता और पोषण परामर्श भी सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे अभियान का प्रभाव सीधे जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है।

अभियान की शुरुआत के समय जून 2025 में जिले के 0 से 5 वर्ष के कुल 55,797 बच्चों को चिन्हित किया गया था, जिनमें से 9,751 बच्चे कुपोषण की विभिन्न श्रेणियों—गंभीर, अति गंभीर और मध्यम—में शामिल थे। यह स्थिति प्रशासन और विभागों के लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन सुनियोजित रणनीति, विभागीय समन्वय और सामुदायिक सहभागिता के चलते इस चुनौती को अवसर में बदला गया। लगातार फील्ड विजिट, घर-घर संपर्क, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मितानिनों और स्वयं सहायता समूहों की सक्रिय भागीदारी तथा अभिभावकों के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव ने अभियान को मजबूती प्रदान की। परिणामस्वरूप मार्च 2026 तक जिले में कुपोषित बच्चों की संख्या घटकर 5,146 रह गई है। गंभीर कुपोषित बच्चों की संख्या 731 से घटकर 328 तथा अति गंभीर कुपोषित बच्चों की संख्या 443 से घटकर 128 हो जाना इस बात का प्रमाण है कि समय पर हस्तक्षेप और सतत निगरानी से गंभीर स्थितियों में भी सुधार संभव है। मध्यम कुपोषण के मामलों में भी उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है, जो समग्र पोषण सुधार की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है।

यदि प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो जून 2025 में जिले में कुपोषण की दर 11.23 प्रतिशत थी, जो मार्च 2026 तक घटकर 7.55 प्रतिशत पर आ गई है। यानी महज कुछ महीनों में 3.68 प्रतिशत की ठोस कमी दर्ज की गई है, जो किसी भी पोषण अभियान के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। इस सफलता के पीछे केवल योजनाओं का क्रियान्वयन ही नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मितानिनों, स्वास्थ्य अमले और स्वयं सहायता समूहों की प्रतिबद्धता, नियमित फॉलोअप और जन-जागरूकता का बड़ा योगदान है। उन्होंने न केवल बच्चों की निगरानी की, बल्कि परिवारों के खान-पान और जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव लाने का भी कार्य किया।

पोट्टु लईका पहल आज केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि सामुदायिक सहभागिता से संचालित एक सशक्त जन-आंदोलन बन चुका है, जिसमें समाज का हर वर्ग बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहा है। यह पहल स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि यदि योजनाओं का क्रियान्वयन संवेदनशीलता, सतत प्रयास और जनभागीदारी के साथ किया जाए, तो कुपोषण जैसी जटिल समस्या पर भी प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार के मार्गदर्शन में इस प्रकार की पहलें राज्य को कुपोषण मुक्त बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा रही हैं और पोट्टु लईका पहल अन्य जिलों के लिए एक अनुकरणीय मॉडल के रूप में स्थापित हो रही है, जो आने वाले समय में प्रदेश के बच्चों के स्वस्थ, सशक्त और सुरक्षित भविष्य की मजबूत नींव तैयार करेगी।

अब मैं उन प्रोजेक्ट्स को चुनती हूं जो मेरे दिल को छूते हैं

अभिनेत्री करिश्मा कपूर लंबे वक्त से बड़े पर्दे से दूर हैं। हालांकि, उनका कहना है कि वो अब समय को ज्यादा महत्व देती हैं और चुनिंदा प्रोजेक्ट्स पर ही काम करना चाहती हैं। हाल ही में अभिनेत्री ने अपने करियर और काम के प्रति अपने जुनून को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि अब वो किस तरह के प्रोजेक्ट्स करना चाहती हैं।

अब मैं समय को ज्यादा महत्व देती हूं करिश्मा कपूर ने दशकों से इंडस्ट्री को करीब से देखने की बात कही। उन्होंने कहा कि आज काम जुनून और उद्देश्य से जुड़ा है। मैं इंडस्ट्री में पली-बढ़ी हूं और मुझे कमर्शियल ब्लॉकबस्टर से लेकर एक्सपेरिमेंटल फिल्मों तक, हर तरह की भूमिकाएं निभाने का सौभाग्य मिला है। अब हर जगह मौजूद रहने के बजाय मैं उन प्रोजेक्ट्स को चुनती हूं जो मेरे दिल को छूते हैं। अभिनेत्री स्वीकार करती हैं कि अब समय उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। उन्होंने कहा कि पहले लगातार काम करने और एक सेट से दूसरे सेट पर जाने की वजह से काफी भागदौड़ रहती थी। अब मैं समय को ज्यादा महत्व देती हूं। मैं सोच-समझकर प्रोजेक्ट चुनती हूं क्योंकि मैं चाहती हूं कि हर प्रोजेक्ट के लिए समय निकालना सार्थक हो और साथ ही परिवार को भी पर्याप्त समय मिल सके। स्क्रिप्ट तो जरूरी है ही, लेकिन साथ ही लोग और कहानी के पीछे का मकसद भी मायने रखता है। अभिनेत्री ने आगे कहा कि बड़े पर्दे का अपना ही जादू है, यहीं से मैंने शुरुआत की थी और यह हमेशा मेरे दिल में एक खास जगह रखेगा। लेकिन मुझे यह भी पसंद है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ कहानी कहने का तरीका कैसे विकसित हुआ है। वेब म्यूजिकल कहानियों और अलग-अलग तरह के किरदारों के लिए मौका देता है। मेरे जैसी किसी के लिए जो आगे क्या करना है, इस बारे में सोच-समझकर फैसला लेती है यह एक बेहतरीन क्षेत्र है। हालांकि, मैं बड़े पर्दे को कभी नहीं छोड़ूंगी।

वर्कफ्रंट की बात करें तो करिश्मा कपूर आखिरी बार साल 2024 में आई मर्डर-मिस्ट्री फिल्म 'मर्डर मुबारक' में नजर आई थी। यह एक मल्टीस्टारर फिल्म थी, जो ओटीटी पर रिलीज हुई थी। हालांकि, फिल्म को खास प्रतिक्रियाएं नहीं मिली थीं। उनके आगामी प्रोजेक्ट को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है।

'कॉकटेल 2' में होगी दीपिका पादुकोण की एंट्री, वेरोनिका के किरदार में करेंगी वापसी?

दीपिका पादुकोण बीते दिनों अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की घोषणा के बाद सुर्खियों में आ गई थीं। इस बीच अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि दीपिका 'कॉकटेल 2' में अपने वेरोनिका के किरदार में वापसी कर सकती हैं। ऐसी चर्चाएं हैं कि दीपिका 'कॉकटेल 2' में अपने 'कॉकटेल' के किरदार में ही कैमियो कर सकती हैं। जानिए आखिर क्यों उठीं ऐसी चर्चाएं हैं और क्या है सच्चाई?

ऐसे शुरू हुईं चर्चाएं

दरअसल, रेडिट पर एक पोस्ट के बाद से ही फैंस के बीच इस बात को लेकर खूब चर्चा हो रही है कि दीपिका 'कॉकटेल 2' में 2012 की 'कॉकटेल' के लोकप्रिय और बिंदास किरदार वेरोनिका में कैमियो करेंगी। पोस्ट के अनुसार, दीपिका कुछ महीने पहले मैडॉक फिल्म्स के ऑफिस गई थीं। उस समय कई लोगों ने अनुमान लगाया था कि यह मुलाकात 'महावतार' से जुड़ी थी। लेकिन पोस्ट में दावा किया गया है कि दरअसल उन्हें सीक्वल में वेरोनिका के किरदार में आने के लिए बार-बार संपर्क किया जा रहा था। उन्होंने इसके लिए हामी भर दी और उसी दौरान अपने हिस्से की शूटिंग भी कर ली।

'कॉकटेल' में दीपिका ने किया था वेरोनिका का किरदार

वेरोनिका दीपिका के सबसे चर्चित किरदारों में से एक है। 2012 में आई 'कॉकटेल' में वेरोनिका अपनी सबसे अच्छी दोस्त मीरा (डायना पेंटी) और उसके लवर गौतम (सैफ अली खान) के साथ लव ट्रायंगल में फंस जाती है। हालांकि, अभी तक दीपिका के फिल्म में कैमियो करने की अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन इस चर्चा ने 'कॉकटेल 2' को लेकर नई हलचल मचा दी है, जो पहले से ही अपनी कास्ट, संगीत और माहौल के लिए ध्यान आकर्षित कर रही है।

19 जून को रिलीज होगी 'कॉकटेल 2'

होमी अदजानिया द्वारा निर्देशित 'कॉकटेल 2' में शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे। यह फिल्म 2012 की 'कॉकटेल' का सीक्वल है। हालांकि, इस बार फिल्म की कहानी बिल्कुल अलग होने की बात कही जा रही है। फिल्म में रोमांस, प्यार और रिश्तों को एक अलग तरह से दिखाया जाएगा। हाल ही में फिल्म का पहला गाना रिलीज किया गया है, जिसे पसंद भी किया जा रहा है। 'कॉकटेल 2' 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

पिता ने लॉन्च करने से किया इनकार, अपने दम पर बनाई अलग पहचान

हिंदी सिनेमा में कई ऐसे कलाकार हुए हैं, जिन्हें परिवार से फिल्मी माहौल तो मिला, लेकिन पहचान उन्हें मेहनत और संघर्ष से बनानी पड़ी। बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मशहूर निर्देशक डेविड धवन के बेटे होने के बावजूद उनके लिए फिल्मों में जगह बनाना बिल्कुल आसान नहीं था। कहा जाता है कि डेविड धवन चाहते थे कि उनका बेटा अपने दम पर आगे बढ़े और खुद मेहनत करके पहचान बनाए। यही वजह थी कि उन्होंने वरुण को अपने बैनर से लॉन्च नहीं किया।

आज वरुण धवन उन कलाकारों में गिने जाते हैं जिन्होंने मेहनत, लगन और लगातार काम के दम पर बॉलीवुड में अपनी खास जगह बनाई। 24 अप्रैल 1987 को मुंबई में जन्मे वरुण धवन फिल्मी माहौल में बड़े हुए। उनके पिता डेविड धवन हिंदी सिनेमा के बड़े निर्देशकों में गिने जाते हैं, जिन्होंने कई सुपरहिट फिल्में बनाई हैं। उनके बड़े भाई रोहित धवन भी निर्देशक हैं। घर में हमेशा बड़े कलाकारों का आना-जाना लगा रहता था। ऐसे माहौल में बड़े होने के कारण वरुण का झुकाव भी फिल्मों की तरफ हो गया। उनके पिता चाहते थे कि वह पहले पढ़ाई पूरी करें।

वरुण ने मुंबई में पढ़ाई करने के बाद इंग्लैंड की नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई खत्म करने के बाद वरुण भारत लौट आए। उस समय हर किसी को लगता था कि डेविड धवन अपने बेटे को बड़े लेवल पर लॉन्च करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डेविड धवन ने साफ कहा कि वरुण को खुद मेहनत करनी होगी। यही वजह रही कि वरुण ने फिल्मों में सीधे अभिनेता बनने के बजाय शुरुआत सहायक निर्देशक के तौर पर की। उन्होंने 'माई नेम इज खान' में करण जौहर के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने फिल्म बनाने की बारीकियां सीखीं और कैमरे के पीछे का काम समझा। इसके बाद, साल 2012 में करण जौहर ने वरुण को 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से लॉन्च किया। इस फिल्म में उनके साथ आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा भी नजर आए। फिल्म बड़ी हिट साबित हुई और वरुण रातोंरात युवाओं के पसंदीदा स्टार बन गए। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 'हम्टी शर्मा की दुल्हनियां', 'बदलापुर', 'एबीसीडी 2', 'जुड़वा 2', 'अक्टूबर' और 'सुई धागा' जैसी फिल्मों में उन्होंने अलग-अलग तरह के किरदार निभाए। खास बात यह रही कि उन्होंने सिर्फ कॉमेडी ही नहीं, बल्कि गंभीर भूमिकाओं में भी अपनी अभिनय क्षमता साबित की।

मृणाल ठाकुर की जगह श्रुति हासन होंगी 'पेद्दी' का हिस्सा

राम चरण की अदाकारी वाली फिल्म 'पेद्दी' जून 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होने से पहले ही काफी चर्चा में है। बुची बाबू सना के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा है। खबरें हैं कि फिल्म के निर्माता श्रुति हासन को लेकर एक स्पेशल गाने की योजना बना रहे हैं।

क्या 'पेद्दी' में कैमियो करेंगी श्रुति हासन?

गल्ट के मुताबिक श्रुति हासन को 'पेद्दी' में एक स्पेशल कैमियो रोल के लिए साइन किया जा सकता है। उम्मीद है कि यह अभिनेत्री एक डांस नंबर में नजर आएंगी, जिसकी शूटिंग अभी बाकी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस गाने की शूटिंग 26 अप्रैल, 2026 को हैदराबाद में शुरू हो सकती है। हालांकि, फिल्म निर्माताओं ने अभी तक श्रुति के इस फिल्म में शामिल होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

मृणाल ने किया मना

इससे पहले, ऐसी खबरें थीं कि इसी स्पेशल डांस नंबर के लिए मृणाल ठाकुर पर विचार किया जा रहा था। लेकिन, अब माना जा रहा है कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लिया है, जिससे अब श्रुति हासन के इस फिल्म में आने की संभावना बढ़ गई है।

'कांतारा' मिमिक्री विवाद में रणवीर सिंह ने कोर्ट से बिना शर्त मांगी माफी

'कांतारा: चैप्टर 1' मिमिक्री विवाद से जुड़े मामले में अभिनेता रणवीर सिंह ने आज कोर्ट में माफी मांगी। रणवीर ने कर्नाटक हाईकोर्ट में संशोधित हलफनामा दाखिल कर बिना शर्त माफी मांगी। अदालत ने रणवीर सिंह की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की गई। यह एफआईआर पिछले साल आयोजित कार्यक्रम में रणवीर द्वारा फिल्म के एक पात्र की मिमिक्री करने और एक मंदिर की देवी के संबंध में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद दर्ज हुई थी। रणवीर सिंह की ओर से एडवोकेट सज्जन पूवैय्या ने अदालत को बताया कि अभिनेता ने बिना शर्त माफी वाला नया हलफनामा दाखिल किया। उन्होंने यह भी कहा कि अभिनेता ने मंदिर जाकर श्रद्धा प्रकट करने का भी आश्वासन दिया।

मामला कानूनी नहीं आस्था से जुड़ा है

शिकायतकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि यह मामला केवल कानूनी विवाद नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था से जुड़ा है। इस पर अदालत ने कहा कि इसी कारण अब तक एफआईआर पर रोक नहीं लगाई गई। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि आदेश में यह दर्ज किया जाएगा कि अभिनेता चार सप्ताह के भीतर मंदिर जाएंगे। साथ ही अदालत ने यह भी संकेत दिया कि वह इस मामले में एक्टर को चेतावनी भी देगी।

हम धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हैं

वहीं रणवीर सिंह की ओर से कहा गया कि वह धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हैं। इसी कारण मामले के गुण-दोष पर बहस नहीं की जा रही है। मामले के अंत में अदालत ने कहा कि वह हलफनामे को रिकॉर्ड पर लेते हुए याचिका का निपटारा करेगी। इससे पहले भी हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि केवल प्रसिद्ध व्यक्ति होने के कारण कोई किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता और सार्वजनिक मंचों पर बोलते समय सावधानी बरतनी चाहिए।

रणवीर शौरी ने बताया करियर पर कैसा पड़ा 'बिग बॉस' का असर

अभिनेता रणवीर शौरी इन दिनों अपने नए प्रोजेक्ट 'एवरीबडी लव्स सोहराब हांडा' को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में अमर उजाला से खास बातचीत में उन्होंने फिल्म, अपने किरदार, करियर, इंडस्ट्री और अपनी सोच पर खुलकर बात की। बातचीत के दौरान, अभिनेता ने बिग बॉस के अपने अनुभव पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि इस शो के बाद उनके करियर में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उन्हें जबर्दस्त पहचान जरूर मिली।

'एवरीबडी लव्स सोहराब हांडा' से जुड़ने की सबसे बड़ी वजह क्या रही?

बहुत सीधा सा जवाब है। एक शब्द में कहूं तो राजत कपूर। और अगर एक नाम और जोड़ना हो तो विनय पाठक। कई बार स्क्रिप्ट से पहले आप उन लोगों पर भरोसा करते हैं, जिनके साथ आप काम करने जा रहे हैं। मुझे पता था कि इन लोगों के साथ कुछ दिलचस्प ही बनेगा। इसलिए यह फैसला बहुत आसान था।

अपने किरदार माधवन के बारे में बताइए

माधवन एक दोस्त है उस ग्रुप का, जिसमें चार पांच कपल्स हैं और सब एक साथ एक एनिवर्सरी हॉलिडे के लिए मिलते हैं। वह दर्शनशास्त्र का प्रोफेसर है। लेक्चर देता है, घूमता है और जिंदगी को बहुत इंटेलेक्चुअल नजरिए से देखता है। उसे लगता है कि उसे इंसानियत की पूरी समझ है। वह बहुत पॉलिश्ड और इवॉल्व्ड इंसान है और सच कहूं तो मुझसे काफी अलग है। लेकिन यही तो दिलचस्प होता है कि आप किसी ऐसे इंसान को निभा रहे होते हैं, जो खुद को बहुत सही समझता है।

क्या आपने किरदार में अपनी तरफ से कुछ जोड़ा

हां, और यह बहुत जरूरी भी होता है। अच्छे डायरेक्टर आपको थोड़ा स्पेस देते हैं। रजत कपूर भी वैसे ही हैं। उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए, लेकिन वह आपको अपनी तरफ से कुछ जोड़ने देते हैं। इस फिल्म में भी कुछ जगह मैंने इम्प्रोवाइज किया और अच्छी बात यह रही कि उन्होंने उसे रखा। एक एक्टर के लिए यह बहुत अच्छा लगता है।

अब आप किस तरह के रोल करना चाहते हैं...

अब मैं चाहता हूं कि मुझे ज्यादा लीड रोल मिलें। जब मैंने शुरुआत की थी तब मैं खुद कहता था कि लीड रोल जरूरी नहीं होते, अच्छे रोल होने चाहिए, रोल छोटा हो या बड़ा उससे फर्क नहीं पड़ता। उस समय यह भी सोचता था कि अगर कैमियो भी है लेकिन क्रिएटिव है, दिलचस्प है, तो वह भी करना चाहिए। मेरे लिए तब काम की क्वालिटी और उसमें क्रिएटिव संतोष ज्यादा मायने रखता था...न कि स्क्रीन टाइम या पोजिशन। लेकिन अब लगभग दस साल हो गए हैं जब मुझे लीड रोल नहीं मिले हैं। तो अब नैचुरली लगता है कि मिलने चाहिए। एक समय के बाद आपको यह महसूस होता है कि आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं.. और शायद आपको उस तरह के मौके नहीं मिल रहे। इसलिए अब चाहत है कि ऐसे रोल आएं जहां मैं कहानी को लीड कर सकूं और अपने आपको उस तरह एक्सप्लोर कर सकूं।

इसके पीछे क्या वजह देखते हैं?

इसमें मेरे हाथ में ज्यादा कुछ नहीं है। मैं न प्रोड्यूसर हूं, न डायरेक्टर। वही लोग तय करते हैं कि किसे कौन सा रोल मिलेगा। हमारे यहां अक्सर आपको उसी तरह के रोल मिलते हैं, जिसमें आप पहले सफल रहे हैं। अगर आपने सपोर्टिंग रोल में ज्यादा सफल फिल्में की हैं तो आपको वही रोल बार-बार मिलते हैं। शायद यही वजह है कि मुझे अब लीड रोल के ऑफर कम मिलते हैं।

नई पीढ़ी के एक्टर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे

नई पीढ़ी के एक्टर्स के लिए मैं यही कहूंगा कि मौके सिर्फ टैलेंट और एबिलिटी के आधार पर मिलते हैं। जेनरेशन के आधार पर कोई फर्क नहीं होना चाहिए। नए एक्टर्स के लिए जरूरी है कि वे अपने काम पर ध्यान दें, अपनी रिस्किल्स पर काम करें और लगातार बेहतर बनने की कोशिश करें। मौके देर से मिलें या जल्दी, लेकिन अगर आपके अंदर काबिलियत है तो वह दिखती जरूर है।

सुशासन तिहार 2026 शासन की सकारात्मक सोच का प्रतीक–कलेक्टर

नई दृष्टिबिंदु / बेमेतरा

कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई की अध्यक्षता मे आज कलेक्टरेट के दिशा सभाकक्ष मे सुशासन तिहार 2026 एवं जनगणना 2027 के संबंध मे प्रेस वार्ता आयोजित हुई` कलेक्टर ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोनों ही पहलें शासन की पारदर्शिता, जवाबदेही और जनकेंद्रित प्रशासन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ श्रीमती प्रेमलता पदमाकर सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

समस्याओं के समाधान का अभियान

कलेक्टर ने बताया कि सुशासन तिहार 2026 शासन की सकारात्मक सोच का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों तक प्रशासन की पहुंच को आसान और प्रभावी बनाना है। इस अभियान के तहत 30 अप्रैल तक सभी विभागों द्वारा योजनाओं के आवेदनों का संतृप्तिकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि इस पहल का मूल उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का त्वरित, गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक निराकरण करना, शासकीय योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना और शासन को सीधे जन–जन तक ले जाना है। कलेक्टर ने बताया की जिले में इस अभियान के अंतर्गत कुल 38 जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इनमें 23 शिविर ग्रामीण क्षेत्रों में और 15 शिविर 11 नगर पंचायतों के नगरीय क्षेत्रों में लगाए जाएंगे। ये शिविर 01 मई से 10 जून 2026 के बीच आयोजित होंगे।

नवाचार से समाधान में तेजी

इस वर्ष भी शिविरों को थीम आधारित बनाया गया है, जिससे विभागवार समस्याओं का बेहतर समाधान हो सके। प्रत्येक शिविर के लिए एक नोडल विभाग निर्धारित किया गया है, जिससे कार्यों में समन्वय, जवाबदेही और त्वरित निराकरण सुनिश्चित होगा। कलेक्टर ने बताया कि शिविरों में नागरिकों से सीधे आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। उन्होंने अपील की कि प्रत्येक समस्या के लिए एक ही आवेदन प्रस्तुत करें तथा आवेदन में सभी आवश्यक जानकारी स्पष्ट रूप से भरें। शिविर स्थल पर आवेदन प्रारूप उपलब्ध रहेगा, जिससे किसी को असुविधा न हो।

शिविरों में प्राप्त सभी आवेदनों का अधिकतम एक माह के भीतर निराकरण किया जाएगा। प्रत्येक आवेदक को उसके आवेदन की स्थिति की जानकारी देना अनिवार्य होगा। साथ ही पूरे अभियान की निरंतर मॉनिटरिंग की जाएगी, शिविरों के बाद समीक्षा बैठकें होंगी और वरिष्ठ अधिकारी फील्ड विजिट कर योजनाओं की जमीनी स्थिति का आकलन करेंगे। इस अभियान के माध्यम से लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण होगा और विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। यह पहल सरकार आपके द्वार की अवधारणा को साकार करती है, जिसमें प्रशासन स्वयं जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करता है।

मकान सूचीकरण व गणना का कार्य

कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने बताया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार जनगणना 2027 का प्रथम चरण 01 मई से 30 मई 2026 तक संचालित किया जाएगा। इस चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा, जिसमें प्रगणक घर–घर जाकर 33 बिंदुओं पर जानकारी एकत्र करेंगे। जिले में 1542 HLB और 1495 प्रगणक तैनात। जिले में कुल 11 नगरीय निकाय और 09 तहसीलों को मिलाकर 20 चार्ज बनाए गए हैं। इसके अंतर्गत 1542 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक तैयार किए गए हैं। कार्य के लिए 1495 प्रगणक और 263 पयर्वेक्षक नियुक्त किए गए हैं। प्रत्येक 6 प्रगणकों पर एक पयर्वेक्षक तैनात रहेगा।

डिजिटल माध्यम से होगी जनगणना

इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल माध्यम से की जाएगी। प्रगणक ल्छड मोबाइल ऐप के जरिए डेटा संकलन करेंगे और सभी कार्यों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। इससे डेटा अधिक सटीक और समय पर उपलब्ध होगा, साथ ही नागरिकों की गोपनीयता भी पूरी तरह सुरक्षित रखी जाएगी।

जनगणना का महत्व और उद्देश्य

कलेक्टर ने बताया कि जनगणना केवल जनसंख्या की गणना नहीं है, बल्कि यह देश के विकास की आधारशिला है। इसके आधार पर स्कूल, अस्पताल और अन्य मूलभूत सुविधाओं की योजना बनाई जाती है। जनगणना का द्वितीय चरण फरवरी 2027 में आयोजित होगा, जिसमें जनसंख्या की गणना की जाएगी ।जनगणना के सफल संचालन के लिए जिले में फ्लेक्स, पोस्टर, पाम्पलेट, एलईडी डिस्प्ले, केबल नेटवर्क और सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जा रहा है। साथ ही प्रगणकों एवं अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा चुका है।

खास खबर

संभाग स्तरीय गोंड समाज को मिला न्याय, 33 साल पुराना रजिस्ट्रेशन मिला वापस

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

संभाग स्तरीय गोंड समाज के पंजीयन का विवाद सुलझ गया है। लगभग 33 वर्ष पुरानी संस्था का पंजीयन क्रमांक 1439 है जो 1993 से पंजीकृत है। समाज के पंजीयन को कुछ लोगों द्वारा फर्जी दस्तावेजों की मदद से हथिया लिया गया। इसके बाद समाज के लोगों ने पंजीयन को यथावत रखने भरपूर प्रयास किया। इसके बाद समाज के लोगों ने अधिवक्ता प्रभांक ठाकुर के जरिए पंजीयक फर्म एवं संस्थाए रायपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार संभाग स्तरीय गोंड समाज के वास्तविक लोगों को उनका पंजीयन वापस मिला। शुक्रवार को समाज के लोगों ने प्रेसवार्ता के माध्यम से इसकी जानकारी साझा की और अधिवक्ता प्रभांक ठाकुर का आभार जताया।

इस पूरे मामले में समाज के अध्यक्ष मोहन सिंह हिडको ने बताया कि समाज के तत्कालीन पदाधिकारियों के द्वारा वर्ष 1998 से 2011 तक की जानकारी सहायक पंजीयक दुर्ग को प्रस्तुत की। 2024 में समाज के प्रेम सिंह धावडे एवं अन्य लोगों ने असत्य जानकारी देकर नागवंशी गोंड समाज का अध्यक्ष बताते हुए सहायक पंजीयक से सूची अनुमोदित करा ली। अधिवक्ता प्रभांक ठाकुर ने पंजीयक को बताया की संविधान की सूची में गोंड जाती दर्ज है ना की नागवंशी गोंड, इससे समाज में भ्रम उतपन्न हो जायेगा तथा जाती प्रमाण पत्र में भिन्नता होने से समाज के लोगों को लाभ मिलने में कठनाई का सामना करना पड़ेगा।

इसके विपरीत दूसरे पक्ष के लोगों ने बताया वे नाग की पूजा करते है इस लिए नागवंशी लिखते है और वर्ष 1983–84 से संस्था चला रहे है। इन लोगों ने दावा किया मृत प्राय संस्था को जीवित कर समाज हित में कार्य कर रहे है इसलिए अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह नेताम, कुमार कोरेटी सुरेश दुग्गा, जगत राम सलामे एवं तुलसी राम मरकाम, मोहन सिंग हिडको आदि को संस्था चलाने का अधिकार नहीं है इसलिए अनुमोदित सूची विधि संमत है। अधिवक्ता प्रभांक ठाकुर ने तर्क दिया की यह लोग 1983–84 से संस्था चलाने का दावा कर रहे हैं जबकि संभाग स्तरीय गोंड समाज पंजीयन क्रमांक का पंजीयन वर्ष 1993 में हुआ है जिससे स्पष्ट है कि दूसरे पक्ष के लोग अलग हैं समाज को भटकाने के लिए संभाग स्तरीय गोंड समाज के नाम का उपयोग कर रहे है जिससे सामजिक व्यव्स्था में विसंगति आयेगी।

अधिवक्ता प्रभांक ठाकुर के तर्क से सहमती जताते हुए पंजीयक फर्म एवं संस्था ने अपने अपील आदेश 24 सितंबर 2025 में सहायक पंजीयक प्रमोद कुजूर द्वारा 28 अक्टूबर 20 24 की प्रेम सिंह धावडे के अध्यक्ष वाली जारी सूची को निरस्त कर दिया। इसके बाद प्रेम सिंह धावडे ने छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के उप सचिव के समक्ष चुनोती दी जिस पर पुनः अधिवक्ता प्रभांक ठाकुर ने सचिव को बताया की संभाग स्तरीय गोंड समाज जिसमे मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र तक के सदस्य है जबकि उत्तरवादी स्वयं को नागवंशी गोंड समाज का अध्यक्ष बताया गया है जो की पंजीकृत नहीं है फिर भी सहायक पंजीयक ने दस्तावेजो का अवलोकन किये बिना उनके द्वारा प्रस्तुत सूची को संभाग स्तरीय गोंड समाज पंजीयन क्रमांक 1439 के नाम से अनुमोदित कर दिया।

उप सचिव ने सुनवाई के दौरान रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाए रायपुर द्वारा दिए आदेश को यथावत रखते हुए संभाग स्तरीय गोंड समाज के पक्ष में निर्णय दिया। समाज के अध्यक्ष मोहन सिंह हिडको ने समाज को बताया की संभाग स्तरीय गोंड समाज सभी वर्गो के संघर्ष के लिए कार्य करता रहेगा तथा गोंड समाज के सभी वर्गो के लिए सदयस्ता अभियान चला कर समाज का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने इस पूरे प्रकरण में अपना पक्ष मजबूती से रखने वाले अधिवक्ता प्रभांक ठाकुर समाज के सभी वर्गो की ओर से आभार जताया।

देश में स्मार्ट मीटरों पर 'प्रीपेड' की अनिवार्यता हुई खत्म, अब उपभोक्ताओं की मर्जी सर्वोपरि

नई दृष्टिबिंदु / नईदिल्ली–लखनऊ

प्रमुख बिंदु: क्या बदलेगा आपके लिए?

अनिवायर्ता खत्म: अब बिजली कंपनियां जबरन किसी के घर में प्रीपेड मीटर नहीं थोप सकेंगी।

सहमति जरूरी: प्रीपेड मोड केवल तभी सक्रिय होगा जब उपभोक्ता इसके लिए अपनी सहमति देगा।

तत्काल प्रभाव: उपभोक्ता परिषद ने मांग की है कि वर्तमान में जितने भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगे हैं, उन्हें तत्काल 'पोस्टपेड' मोड में बदलने का विकल्प दिया जाए।

अधिकारों की रक्षा: यह कदम बिजली चोरी रोकने के साथ–साथ उपभोक्ता के अधिकारों के बीच संतुलन बनाएगा।

मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करवाने में प्रमुख भूमिका रखने वाले नरेन्द्र डाकलिया ने बताया कि उपभोक्ता के हितों में कार्य रत संस्थाओं की सक्रियता से देश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। उपभोक्ता हितों के लिए लंबे समय से जारी संघर्ष के बाद केंद्र सरकार और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अपनी नीति में बड़ा बदलाव किया है। अब देश में स्मार्ट मीटर तो लगाए जाएंगे, लेकिन उन्हें 'प्रीपेड' मोड में चलाना अनिवार्य नहीं होगा।

1 अप्रैल 2026 से नई व्यवस्था लागू

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 1 अप्रैल 2026 को एक नई अधिसूचना जारी की है। इस संशोधन के अनुसार, जिन क्षेत्रों में संचार नेटवर्क मौजूद है, वहां स्मार्ट मीटर तो लगाए जाएंगे, लेकिन उपभोक्ताओं को प्रीपेड या पोस्टपेड चुनने का विकल्प दिया जाएगा। पहले सरकार ने प्रीपेड मोड को अनिवार्य कर दिया था, जिसका देशभर में विरोध हो रहा था।

विद्युत अधिनियम 2003 का हवाला

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष और सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने इसे उपभोक्ताओं की ऐतिहासिक जीत बताया है। उन्होंने कहा: "राष्ट्रीय कानून 'विद्युत अधिनियम 2003' की धारा 47(5) के तहत उपभोक्ताओं के पास प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों के विकल्प मौजूद हैं। पहले के आदेश इस कानून का उल्लंघन कर रहे थे, जिसे अब सुधार लिया गया है।"

उपभोक्ता परिषद का संघर्ष लाया रंग

ज्ञात हो कि बिजली कंपनियां उएअ के पुराने आदेश का हवाला देकर हर जगह प्रीपेड मोड लागू कर रही थीं। उपभोक्ता परिषद ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और ऊर्जा सचिव के समक्ष इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठकों में दी गई दलीलों के बाद अंततः भारत सरकार ने अपनी गलती सुधारते हुए नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इस फैसले से साफ है कि अब देश में बिजली व्यवस्था 'मोबाइल रिचार्ज' की तरह केवल प्रीपेड नहीं रहेगी, बल्कि उपभोक्ताओं को उनकी सुविधा के अनुसार भुगतान करने की आजादी होगी।

सर्व अनु.जाति व अंबेडकरी समाज की विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से भेंट

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

छत्तीसगढ़ में विभिन्न अनु.जाति वर्ग एवं अंबेडकरी समाज का एक प्रतिनिधि मंडल ऑल PSU एससी/ एसटी फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील रामटेके के नेतृत्व में विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भेंट कर मांग की। जिसमें सर्व प्रथम प्रदेश में बसे देश विभिन्न राज्यों के बसे अनु. जाति वर्गो के जो लोग यहां निवास कर रहे हैं उनके जाति प्रमाण पत्र जिसकी मांग विगत 25 वर्षो से कर रहे है। इस पर चर्चा कर मांग की।

छत्तीसगढ़ में बौद्ध एवं अंबेडकरी समाज के लाखों लोग विगत 50 वर्षो से भी अधिक वर्षो से निवास कर रहे हैं, शासन ने समाज में किसी भी व्यक्ति को प्रतिनिधित्व नहीं दिया इस पर विश्व की सबसे बड़ी बुद्धिस्ट धरोहर सिरपुर में इस समाज के वरिष्ठ प्रतिनिधि के योग्यता के आधार पर प्रतिनिधि दिया जाए। छत्तीसगढ़ में सभी समाज के लोगों को शासन में प्रतिनिधित्व दिया है, किन्तु बौद्ध समाज को कहीं भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला है।

छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़, सिरपुर, भोंगापाल (आदिवासी क्षेत्र) को सवोच्च पर्यटन स्थल बनाकर अंगीकार किया जाए। आजादी के 75 वर्षो के पश्चात आज भी वंचित समाज के लोगों पर अनदेखी हो रहे है, जिसपर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा सुनियोजित क्रियान्वयन किया जावे। प्रदेश में उपरोक्तवर्गो के हजारों योग्य छात्र छात्राएं अध्ययनरत है, जिनको योग्यता के आधार पर सरकारी पदों पर नियुक्ति की जाए। छत्तीसगढ़ गाढ़ा, उड़िया, बसोड, रविदास समाज आदि वर्गो की समस्या विधिवत निराकरण किया जावें। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य विभिन्न समस्याओं पर भी चर्चा हुई।

नीट विद्यार्थियों के लिए सेवा का संकल्प बना जनप्रेरणा का सशक्त केंद्र

आर्य समाज की प्रेरणा से हो रहा है कार्य, पानी, परवाह और प्रेरणा हेमा सक्सेना टीम का सेवा अभियान बना जीवंत उदाहरण

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

नीट परीक्षा के मद्देनजर विद्यार्थियों की सुविधा और सेवा हेतु एक सराहनीय और प्रेरणादायी पहल तेजी से आकार ले रही है। इस पुनीत कार्य में हेमा सक्सेना विशेष भूमिका निभाते हुए अपनी टीम के साथ विभिन्न चयनित परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित रूप से अंतिम रूप दे रही हैं।

भीषण गर्मी और परीक्षा के दबाव के बीच विद्यार्थियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्रों पर ठंडे पानी की बोतलें नमकीन और बिस्कुट जैसी आवश्यक सुविधाओं की सुदृढ़ व्यवस्था की जा रही है जिससे उन्हें मानसिक संतुलन और शारीरिक ऊर्जा बनाए रखने में सहायता मिल सके।

इस सेवा अभियान में आचार्य डॉ अजय आर्य की प्रेरणा से अनेक समर्पित कार्यकर्ता पूरे उत्साह और निष्ठा के साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही आर्य समाज मंदिर सेक्टर–6 जुलाई अध्यात्म पथ दिल्ली आर्य वीर दल और वैदिक सत्संग समिति का सहयोग इस अभियान को और अधिक सशक्त बना रहा है।

अंतरराष्ट्रीय कथाकार आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री ने अपने विस्तृत उद्बोधन में कहा कि सेवा केवल दान या सहायता भर नहीं है बल्कि यह आत्मशुद्धि का एक गहन माध्यम है। उन्होंने कहा कि योगी वर्षो तक साधना करते हैं तब जाकर मन को निर्मल बना पाते हैं, लेकिन निस्वार्थ सेवा वही कार्य सहज रूप से कर देती है। सेवा व्यक्ति के भीतर करुणा, विनम्रता और त्याग का भाव विकसित करती है और समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है, उसका हर कर्म एक साधना बन जाता है और वही सच्चे अर्थो में मानवता का उपासक कहलाता है। आज सेवा कार्य का अवलोकन करने पहुंचे आचार्य डॉ. अजय आर्य ने टीम की समर्पित भावना की सराहना करते हुए हेमा सक्सेना को पुष्प भेंट कर सम्मानित किया।

अपने चुटीले और विचारोत्तेजक अंदाज में आचार्य डॉ अजय आर्य ने कहा कि आज के दौर में लोग स्वयं को दिखाने में अधिक व्यस्त हैं लेकिन सच्ची पहचान सेवा से बनती है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि सेल्फी में हम अपने चेहरे को सजाते हैं और सेवा में अपने चरित्र को संवारते हैं। आगे उन्होंने जोड़ा कि ईश्वर को पाने के लिए बड़े–बड़े प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, यदि मन में निस्वार्थ सेवा का भाव है तो वही सबसे बड़ी पूजा है। उन्होंने यह भी कहा कि सेवा केवल अवसर नहीं बल्कि जिम्मेदारी है, और जो व्यक्ति इस जिम्मेदारी को समझ लेता है वह अपने जीवन को सार्थक बना लेता है।

इस अवसर पर हेमा सक्सेना ने भावुक शब्दों में कहा कि आचार्य जी ने उन्हें सेवा का मार्ग दिखाया है और वे अपने व्यक्तिगत जीवन में निरंतर यह प्रयास करती हैं कि अपने आसपास के वातावरण को अधिक सुंदर अधिक संवेदनशील और अधिक मानवीय बनाया जा सके। यह सेवा अभियान न केवल विद्यार्थियों के लिए सहायक सिद्ध हो रहा है बल्कि समाज में सहयोग संवेदनशीलता और सकारात्मक ऊर्जा का सशक्त संदेश भी प्रसारित कर रहा है।

सहयोगकर्ताओं के नाम

राजकुमार भल्ला, डॉ आर के मल्होत्रा, के के शर्मा, धमर्पाल खंडूजा, डोनोडे जी, जी एस ठाकुरेल, परमवीर भल्ला, रवि आर्य, शिपी आर्य, गुप्त दान, सरपाल जी, सुदर्शन गुप्ता, डॉ अनुपम मौर्य, संजीव कुमार भल्ला, प्रेम लता ठाकुर, रीना गुप्ता, रश्मि सरीन, कमलेश आर्य, भारती जुल्का, शौर्य आर्य, शशिलता, वीना भोई, पवन चोपड़ा, अनुपम सिंह, शशि गोयल, गुलबीर, ओमप्रकाश जांगिड़, अनीता भारद्वाज, नीता दास, आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री, लेखराम साहू, पूजा गंगवानी, राजेश्वरी ठाकुर, आशीष सक्सेना, ओजस्वी सक्सेना, राहुल कुमार लोध, बिंदु श्रीवास्तव, पूजा श्रीवास्तव, विकास मालानी, सबिता साहू, आनन्या अग्रवाल, गौरव नायक, राहुल कुमार साहू, आभा शर्मा, प्रदीप यादव, कल्पना सुक्ला, रिचा श्रीवास्तव, भारती सक्सेना, नंदिता सक्सेना, जिया मनीष, डॉ आशी मिश्रा शामिल हैं।

छग चैंबर ऑफ कॉमर्स दुर्ग ने किया मेहनतकश हाथों का सम्मान

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

1 मई को छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स, दुर्ग द्वारा तहसील के सामने दुर्ग वह सिंधी धमर्शाला के पास मजदूर दिवस के अवसर पर मेहनतकश मजदूर भाई–बहनों का सम्मान किया गया। इस दौरान दिहाड़ी श्रमिक, निर्माण कार्य में लगे मजदूर, ठेला–खोमचा संचालक, छोटे व्यवसायी एवं श्रम से जुड़े सभी वर्गो को सम्मान स्वरूप उपहार भेंट कर उनके परिश्रम और योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई।

कार्यक्रम की शुरुआत में चेंबर ऑफ कॉमर्स दुर्ग के जिला अध्यक्ष अनूप गटागट ने कहा – मजदूर हमारे समाज और अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। उनके अथक परिश्रम से ही विकास का हर मार्ग प्रशस्त होता है। मजदूर दिवस केवल एक दिन नहीं, बल्कि उन सभी मेहनतकश हाथों के सम्मान का अवसर है जो अपने पसीने से समाज को आगे बढ़ाते हैं।

इसके पश्चात शिव चंद्राकर ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा –हर मेहनतकश व्यक्ति सम्मान का अधिकारी है। मजदूरों का योगदान केवल निर्माण और व्यापार तक सीमित नहीं, बल्कि समाज के हर क्षेत्र में उनका योगदान अमूल्य है। हमें हमेशा उनके सम्मान और अधिकारों के लिए आगे आना चाहिए।

वहीं किशोर जैन ने कहा – छोटे व्यवसायी, ठेला–खोमचा चलाने वाले और श्रमिक वर्ग हमारे समाज की आत्मा हैं। उनका संघर्ष, समर्पण और मेहनत हम सभी के लिए प्रेरणा है। ऐसे कार्यक्रम समाज में संवेदनशीलता और सहयोग की भावना को मजबूत करते हैं।

इस अवसर पर चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों द्वारा मजदूर भाई–बहनों का गमछा पहनाकर आत्मीय स्वागत किया गया तथा उपहार स्वरूप भेंट(गिफ्ट) प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया गया। इसके साथ ही पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर मजदूरों से संवाद स्थापित किया और उनका उत्साहवर्धन किया। पूरे कार्यक्रम में सेवा, सम्मान और संवेदनशीलता की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई दी।

इस आयोजन में चेंबर के पदाधिकारी, सदस्यगण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे, जिनमें जिला अध्यक्ष अनूप गटागट , शिव चंद्राकर ,प्रहलाद रुंगटा ,किशोर जैन ,कुलदीप सिंह ,दिनेश टावरी ,दर्शन ठकवानी ,उत्तम भंडारी ,अरुण दुग्गड़ , आनंद अग्रवाल ,जवाहर जैन ,मनोज अग्रवाल ,सुदीप अग्रवाल ,दिलीप मरोठी ,मुरली सचदेवा ,बहादुर अली ,आशीष सक्सेरिया ,आनंद जैन ,उदय शंकर त्रिपाठी ,योगेश बरडिया ,राजीव अग्रवाल ,आशीष लुनिया ,डॉ. मानसी गुलाटी ,नीतू श्रीवास्तव ,रूपलता साहु ,अनिमा सिंग ,दीना सोनी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

छात्रों ने की कुशाभाऊ ठाकरे विवि का भ्रमण

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

छत्तीसगढ़ कृषि महाविद्यालय धनौरा भिलाई के बीएससी कृषि के चतुर्थ वर्ष के छात्र–छात्राओं ने ग्रामीण पत्रकारिता और व्यवहार कौशल विषय के अंतर्गत कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय काठाडीह (रायपुर) का टीवी स्टूडियो और सामुदायिक रेडियो 90.8 रेडियो संवाद का शैक्षणिक भ्रमण किया।

इस विशेष सत्र में कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर के कुलपति प्रो. मनोज दयाल ने कृषि पत्रकारिता और व्यवहार कौशल विषय पर विद्यार्थियों से इंटरेक्शन (संवाद) किया। प्रो. दयाल ने कहा कि शहरों की अपेक्षा ग्रामीण भारत में समाचार पत्रों का ग्रोथ परसेंटेज बढ़ा है। रेडियो की रीच और टार्गेट आडियंस में पहुंच आए दिन बढ़ रही है। इंटरनेट के विकास के साथ सोशल मीडिया का इंफ्यूलेंस बढ़ा है। कृषि प्रधान भारत में दुरदर्शन टीवी माध्यम का ग्राम विकास और उन्नत कृषि में योगदान का उदाहरण हम सबके सामने है।

छत्तीसगढ़ कृषि महाविद्यालय, भिलाई के विद्यार्थियों को प्रो. मनोज दयाल ने कहा कि किसानों के कम्युनिकेशन बिहेवियर का अध्ययन कृषि पत्रकारिता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें आपको 7 सी फार्मूला पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। कृषि विज्ञान और कृषि पत्रकारिता के छात्र के रूप में आप सभी का सुनहरा और उज्जवल भविष्य है। कृषि अर्थव्यवस्था में कृषि पत्रकारिता का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके लिए प्रमुख तत्व है– ग्रामीणों की क्रय शक्ति का विकास, जन जागरूकता और समाचार पत्रों के साथ इंटरनेट की गांवों तक पहुंच। आज ग्रामीण भारत में लगभग 550 मिलियन युजर्स है। वे सूचना क्रांति के माध्यम से गांवों की नई तस्वीर गढ़ रहे हैं।

सत्र को विश्वविद्यालय के कुलसचिव सुनील कुमार शर्मा, पत्रकारिता के विभागाध्यक्ष पंकज नयन पाण्डेय, अनिल कुमार मिश्र और छग कृषि महाविद्यालय के विवेक कुमार पाण्डेय ने संबोधित किया। टीवी स्टूडियो में कृषि छात्रों ने एक किसान टॉक शो का आयोजन किया जिसमें वैभव सिंह,पुष्पेन्द्र प्रताप सिंह ,अन्वी तिवारी , हिमांशू वर्मा गुलशन मिश्रा , नारायणी देवांगन, दिव्या देशमुख, शिक्षा मिश्रा,श्वेता बिंजलेकर, एन के रेड्डी, आकांक्षा बेन, ऐश्वर्या निलोल, रिया शर्मा, लक्ष्मी साहू, सुजीत चतुर्वेदी ने डच रोज, ग्वावा फार्मिंग, मॉडर्न फार्मिंग,,लाख कल्टीवेशन, मशरूम फार्मिंग, सेरीकल्चर विषय में किसान भाइयों को पूरे जोश और विश्वास के साथ अनेक जानकारी प्रदान की।

700 सफाई कामगारों की छंटनी की साजिश, भिलाई को 'नरक' बनाने पर तुले भोजराज सिन्हा : लक्ष्मीपति राजू

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

नगर पालिक निगम भिलाई के खाद्य, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विभाग के अध्यक्ष (MIC सदस्य) लक्ष्मीपति राजू ने भाजपा पार्षद भोजराज सिन्हा और निगम आयुक्त राजीव पांडेय के बीच पनपी कथित 'सांठगांठ' पर सीधा हमला बोला है। श्री राजू ने दो टूक कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए आयुक्त और भाजपा पार्षद के बीच जो 'नूरा-कुश्ती' चल रही है, उसका खामियाजा भिलाई की जनता को भुगतने नहीं दिया जाएगा।

आयुक्त की 'बोली' बोल रहे भोजराज सिन्हा

लक्ष्मीपति राजू ने कटाक्ष करते हुए

कहा कि जो प्रशासनिक आदेश अब तक न MIC में आया, न सामान्य सभा के पटल पर रखा गया, वह गोपनीय फाइल भाजपा पार्षद के पास कैसे पहुँच गई? क्या अब निगम के दफ्तर पार्षदों के ड्राइंग रूम से चल रहे हैं या आयुक्त खुद सरकारी दस्तावेज 'प्रसाद' की तरह बांट रहे हैं?

वार्डों में मचेगा हाहाकार : हर वार्ड से कटेंगे 15 कर्मचारी

श्री राजू ने इस नए प्रस्ताव के घातक परिणामों को रेखांकित करते हुए कहा कि— "आयुक्त का नया फॉर्मूला लागू होते ही प्रत्येक वार्ड से औसतन 15-15 सफाई कर्मचारियों की कटौती हो

आमने-सामने की लड़ाई

जाएगी। जब हर वार्ड से 15 अनुभवी हाथ कम होंगे, तो गलियों में कचरे का अंबार लगना तय है। इससे न केवल सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी, बल्कि शहर के हर वार्ड के पार्षद भी असहाय हो जाएंगे क्योंकि उनके पास जनता की शिकायतों के समाधान के लिए पर्याप्त मैनपावर ही नहीं बचेगा। यह सीधे तौर पर भिलाई को गंदगी के ढेर में धकेलने और जन-आक्रोश को भड़काने की तैयारी है।"

700 परिवारों के चूल्हे बुझाने की साजिश

श्री राजू ने बताया कि शहर के वार्डों की कमान 2000 से अधिक जांबाज सफाई कर्मियों के हाथ में है। आयुक्त के नए फॉर्मूले से करीब 700-800 गरीब कामगारों की रोजी-रोटी छिन जाएगी। उन्होंने व्यंग्य किया— "भोजराज जी, क्या आपकी राजनीति इतनी गिर गई है कि गरीबों के पेट पर लात मारकर आप आयुक्त की 'गुड बुक' में आना चाहते हैं? जिनका रोजगार जाएगा, उन परिवारों की बद्दुआएं आप कैसे झेलेंगे? अगर ये श्रमिक सड़कों पर उतरे, तो क्या उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे?"

'सेटिंग' के फेर में निगम पर करोड़ों का बोझ!

लक्ष्मीपति राजू ने आर्थिक नुकसान पर सवाल उठाते हुए कहा कि वर्तमान में सफाई का पूरा जिम्मा एजेंसी के पास है, जिसमें संसाधन (गाड़ी-झाड़ू) उन्हीं के होते हैं। लेकिन इस नए प्रस्ताव में संसाधनों और डीजल का सारा खर्च निगम की जेब पर डाल दिया जाएगा, जो वर्तमान खर्च से कहीं अधिक होगा। क्या यह जनता के पैसे की बर्बादी कर किसी विशेष 'सेटिंग' को साधने की कोशिश है?

पिछली दो पारियों में क्यों मौन थे 'ज्ञानी' भोजराज?

एमआईसी सदस्य ने याद दिलाया कि भोजराज सिन्हा पिछले दो बार से पार्षद हैं, लेकिन तब उन्हें सफाई में कोई खामी नजर नहीं आई। आज अचानक पैदा हुई यह 'चिंता' शहर के लिए नहीं, बल्कि आयुक्त के साथ मिलकर की जा रही 'साझेदारी' का हिस्सा है।

कड़े शब्दों में चेतावनी

अंत में श्री राजू ने कड़े शब्दों में आगाह किया कि भोजराज सिन्हा अपनी ही पार्टी के पार्षदों का विश्वास खो चुके हैं। यदि भिलाई की सफाई व्यवस्था चरमराई, वार्डों में गंदगी से जनता परेशान हुई या श्रमिकों के आंदोलन से शहर की शांति भंग हुई, तो इसके लिए सीधे तौर पर आयुक्त राजीव पांडेय और उनकी ढाल बने भोजराज सिन्हा जिम्मेदार होंगे।

मजदूरों के लिए नहीं पूंजी पत्तियों के लिए कार्य कर रही भाजपा की डबल इंजन सरकार- भूपेश बघेल

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

1 मई मजदूर दिवस पर ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस अध्यक्ष क्षितिज चंद्राकर के नेतृत्व में आयोजित बोरे बासी तिहार में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित जिले के तीनों जिलाध्यक्ष धीरज बाकलीवाल , राकेश ठाकुर, मुकेश चंद्राकर के साथ सभी वरिष्ठ नेता गण शामिल हुवे। मजदूर दिवस के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर सीधा प्रहार करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य की भाजपा की डबल इंजन सरकार मजदूर किसान के लिए नहीं बल्कि पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही है।

उन्होंने कहां की आजादी के बाद कांग्रेस शासन में हजारों उद्योगों की स्थापना हुई जिसमें करोड़ों लोगों को रोजगार मिला लेकिन भाजपा के प्रदेश के 18 वर्ष और केंद्र के 12 वर्ष के शासन में केवल उद्योगों को बेचने का और मजदूरों को बेरोजगार करने का कार्य कर रही है भाजपा सरकार इसका प्रत्यक्ष उदाहरण दुर्ग जिले में भिलाई इस्पात संयंत्र है जिसमें कांग्रेस शासन में 1980 में 60000 नियमित कमचारी होते थे जो आज केवल उनकी संख्या 12000 हो गई है। अभी सेक्टर 9 हॉस्पिटल को भी निजीकरण करने की तैयारी कर रही है कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है वर्तमान सरकार केवल जल जमीन जंगल और उद्योगों को बेचने का कार्य कर रही है और मजदूरों को बेरोजगार कर रही है।

कार्यक्रम के आयोजक क्षितिज चंद्राकर ने कहा कि भाजपा की सरकार मजदूर गरीबों का शोषण ही किया है मनरेगा में कटौती कर कार्य दिवस को कम कर ग्रामीणों के रोजगार को खत्म कर दिया गया । रोजगार के लिए छत्तीसगढ़ के किसान और मजदूरों को यहां से पलायन करना दिखता है कि यहां मजदूरों की क्या स्थिति है ।

दुर्ग शहर अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल ने कहा कि बोरे बासी हमारे मजदूर किसानों का आहार है छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपरा और पहचान को आगे बढ़ाने का कार्य कांग्रेसीन किया है । कांग्रेसी ऐसी पार्टी है जो मजदूर गरीब किसान सभी वर्ग का सम्मान करती है और सबके हितों की रक्षा करने का कार्य करती है।

जिला ग्रामीण अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने कहा प्रदेश की भाजपा सरकार को आम जनता की मजदूरों की किसानों की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है प्रदेश नशे में डूबता जा रहा है दुर्ग जिले सहित प्रदेश में अपराध बढ़ता जा रहा है एक ही दिन में जिले में पांच हत्या होना जिले की कानून व्यवस्था को दिखाता है और प्रदेश के गृह मंत्री सहित पूरे विधायक मंत्री प्रदेश को छोड़कर बंगाल चुनाव में प्रचार में व्यस्त रहे ।

बोरे बासी मजदूर दिवस में प्रमुख रूप से भिलाई जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर पूर्व विधायक प्रतिमा चंद्राकर पूर्व सदा अध्यक्ष लक्ष्मण चंद्राकर प्रदेश महामंत्री राजेंद्र साहू दीपक दुबे जितेंद्र साहू महापौर नीरज पाल शशि सिन्हा, पूर्व महापौर आर एन वर्मा राजेश यादव अल्ताफ अहमद देवेंद्र देशमुख संजय कोहले, अय्यूब खान, गुरदीप भटिया , आनंद ताम्रकार, देव श्री साहू, मनीष बघेल, प्रवक्ता नासिर खोखर, अनूप वर्मा जयंत देशमुख गौरव उमरे, दीप सारस्वत सिद्धार्थ चंद्राकर दीपक जैन अनमोल पवन चौबे गोलू गवाने आशुतोष सिंह , आयुष शर्मा, निकिता मिलिंद, राजू भाटिया, तुषार कुमार रोहन राय सिंह दिकोलां , अब्दुल गनी, अजय शर्मा प्रेमलता साहू धनंजय साहू मीना पाल बिंदु राजपूत खुशबू साहू अमोल जैन यस बाकलीवाल राजकुमार पाली अजय मिश्रा, सुशील भारद्वाज, अजय राज शर्मा, धनंजय साहू, सुनीत घोष सीजू एंथोनी केशव सिंह संजू धनकर विनोद सेन, मीन पॉल, रतन नरमदेव जमुना साहू कन्या डिमर, राजकुमार नारायणी, सौरभ ताम्रकार, सहित दुर्ग शहर , दुर्ग ग्रामीण, भिलाई शहर के अन्य सैकड़ों कांग्रेसी उपस्थित रहे ।

अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर बोरे बासी त्योहार का हुआ चकनार में भव्य आयोजन

नई दृष्टिबिंदु / खैरागढ़

जिस प्रथा की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस शासनकाल में 01 मई मजदूर दिवस के दिन बोरे बासी तिहार के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। उसी के मद्देनजर रखते हुए एक भव्य रूप से कार्यक्रम का आयोजन खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिला के गंडई ब्लाक के ग्राम चकनार के दैहान चौक में आयोजित बोरे बासी त्योहार का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री रविन्द्र चौबे, वरिष्ठ कांग्रेसी गिरीश देवांगन, विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा, को फूलो का गजमाला पहनाकर स्वागत किया गया। उसके बाद मंचीय कार्यक्रम संपन्न हुआ।

जिसमें बोरे बासी त्यौहार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा की भाजपा सरकार गांव के किसान के उपजाऊ जमीन को बंजर बनाकर इसमें उद्योग डाल रही है। जिससे गांव के लोगो को धुएं,धूल और बीमारी परोसा जाएगा,कांग्रेस के शासन काल में भूपेश बघेल ने इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास किया है और भाजपा के सरकार के ढाई साल में सिर्फ लोगो को लड़वाने का काम किया है। गांव-गांव में स्कुल को बंद कर शराब दुकान खोल रही है। यही है भाजपा का असली चेहरा, कार्यक्रम में विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा ने सभी उपस्थित मजदूरों को बोरे बासी की शुभकामना देते हुए प्रदेश के भाजपा सरकार को आड़े हाथ लेते हुए जमकर कोशा,और कहा की घुमका के गौ गौठान में भाजपा सरकार दारू भट्ठी का संचालन कर रहा है। इससे ज्यादा विकास और क्या हो सकता है, भाजपा सरकार परिवार को लड़ाने का काम कर रही है, कांग्रेस को भाजपा पार्टी के नेता बोलते है, की कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण का विरोध करते है,जबकि वर्ष 2023 में आरक्षण का विरोध उन्होंने किया है।

कांग्रेस की संपत्ति का विनाश भाजपा सरकार और उनके कार्यकर्ता कर रही है।। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अधिवक्ता हेमंत वैष्णव ने किया। कार्यक्रम में दर्शकों के मनोरंजन के लिए छत्तीसगढ़ लोक कला मंच मया के डोरी काचरी वाले का कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम के अंत में सभी ने बोरे बासी का आनंद लिया। कार्यक्रम में आलोक चंद्राकर, जिला कांग्रेस राजनांदगांव के पूर्व अध्यक्ष पदम कोठारी, पूर्व विधायक गिरवर जंघेल ,ब्लॉक अध्यक्ष मन्नू चंदेल, संजू सिंह चंदेल, कामदेव जंघेल, महिला कांग्रेस की जिला उपाध्यक्ष हेमलता ठाकुर, रमेश साहू पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष रुक्मणी देवांगन, पार्षद दिलीप ओगरे, विजय वर्मा, वरिष्ठ कांग्रेसी मोती जंघेल ,अय्यूब कुरैशी, सोनल क्रांति ताम्रकार,अमन सोनी, अमित टंडन,तानसेन साहू, वेदांत यदु, सरपंच वंदना लालचंद पटेल, सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

आज इन इलाकों में वज्रपात और आंधी-तूफान की चेतावनी जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। आसमान में बादल छाने से अधिकतम तापमान में गिरावट आई है। इसके अलावा अगले 4 दिनों तक सभी संभागों में एक-दो स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बादल गरजने, वज्रपात और हल्की वर्षा होने की संभावना है। शुक्रवार को प्रदेश में एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा हुई। सबसे ज्यादा गर्मी का सामना दुर्ग के लोगों ने किया, यहां 43.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 24.11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग ने आज एक-दो स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात और तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की है। दो दिन बाद हल्की बारिश हो सकती है। गरज चमक के साथ वज्रपात होने तथा तेज हवा (40-50 KMPH) चलने की संभावना है। राजधानी में आज बादल गरजने के साथ बारिश हो सकता है। मौसम विभाग ने शनिवार को आसमान में बादल छाए रहने की संभावना जताई है। अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।

मजदूर दिवस पर संयुक्त खदान मजदूर संघ की भव्य बाइक रैली व आमसभा सम्पन्न, श्रमिक एकता का दिया संदेश

नई दृष्टिबिंदु / नंदिनी अहिवारा

अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर संयुक्त खदान मजदूर संघ (एटक) द्वारा आयोजित बाइक रैली एवं साधारण सभा का कार्यक्रम पूरे उत्साह, अनुशासन और श्रमिक एकता के संदेश के साथ सम्पन्न हुआ। इस आयोजन में क्षेत्र के बड़ी संख्या में श्रमिकों ने भाग लेकर अपनी एकजुटता का परिचय दिया।

कार्यक्रम की शुरुआत एस.के.एम.एस. कार्यालय से शाम 6 बजे बाइक रैली के साथ हुई। रैली में शामिल श्रमिकों ने हाथों में झंडे एवं बैनर लेकर श्रमिक अधिकार, सुरक्षा और सम्मान से जुड़े नारे लगाए। यह रैली अहिवारा अटल चौक से होते हुए टाउनशिप नंदिनी नगर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करती हुई पुनः एस.के. 45 कार्यालय पहुंची। रैली के दौरान क्षेत्रवासियों में भी उत्साह देखा गया और श्रमिकों के प्रति समर्थन का माहौल बना।

रैली के समापन के बाद यूनियन कार्यालय में साधारण सभा का आयोजन किया गया। सभा में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, कार्यस्थल पर सुरक्षा व्यवस्था, वेतन एवं सुविधाओं में सुधार, तथा संगठन की मजबूती जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि मजदूर दिवस केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि श्रमिकों के संघर्ष, अधिकारों और सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने सभी श्रमिकों से संगठित रहने और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने का आह्वान किया।

कार्यक्रम में अध्यक्ष रोहित वर्मा, सचिव बी.आर. पटेल, एम.सी. कटारे, भूपेंद्र वर्मा, प्रेम साहू, विनीत यादव, रामबाबू पांडे, सनत शर्मा, मोती शर्मा, शिवकुमार निषाद, हनुमान साहू, धर्मेंद्र प्रसाद, डी.डी. पटेल, राजू अशवन, लक्ष्मण साहू, भवन साहू, अमित, सुभाष वर्मा, सूरज साहू, संतोष वर्मा, ओम कोसरे, टीकम, पुरुषोत्तम साहू, राजू सिंग, भीकम, हाबिद, भूपेंद्र, महेश सोंधिया सहित अनेक पदाधिकारी एवं श्रमिक साथी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

अंत में संघ पदाधिकारियों ने सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन से श्रमिकों में जागरूकता बढ़ती है, आपसी एकता मजबूत होती है और संगठन को नई दिशा मिलती है।

"यह समाचार पत्र आलोक तिवारी द्वारा 80/बी, मैत्री विहार, राधिका नगर, सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग, (छत्तीसगढ़)-490023 से आलोक तिवारी की ओर से प्रकाशित की जाती है, जिसका संपादन आलोक तिवारी द्वारा किया जाता है तथा इसका मुद्रण समय दर्शन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स द्वारा प्लॉट नं. 339/6, गली नं. 02, पाटन, थाना उतई, दुर्ग, (छ.ग.)-491111 पर किया जाता है। (समाचार चयन के लिए PRP Act, 2023 के तहत संपादक जिम्मेदार है)। समस्त विवादों का निपटारा न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।" संपादक आलोक तिवारी, मो. 74154-69100